



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2003/माघ 24, 1924

No. 48]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2003/MAGHA 24, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2003

अंतिम जांच परिणाम

विषय: यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के या वहां से निर्यातित फिनोल के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 14/4/2002-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा

सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार।

क. प्रक्रिया

जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० (एम ओ सी एल) से लिखित याचिका प्राप्त हुई है, जिसमें यूरोपीय संघ, सिंगापुर तथा दक्षिण अफ्रीका (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था।

(ख) प्राधिकारी ने उक्त नियम-5 के उप-नियम-5 के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन की प्राप्ति के विषय में भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को सूचित किया।

(ग) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 तथा 27 के तहत सीमाशुल्क उपसीर्य सं. 2907.11 तथा 2707.60 के अंतर्गत आने वाले फिनाल के आयातों से संबंधित पाटवरोधी कार्यवाही शुरू करने के बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे 15 फरवरी 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया।

घ) प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयात से संबंधित पाटवरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक जांच परिणामों को दिनांक 24.6.2002 की अधिसूचना सं. 14.4.2002-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किया था तथ हितबद्ध पार्टियों से यह अनुरोध किया था कि वे इसके प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के अंदर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।

(ङ.) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अग्रेषित की तथा उनसे यह अनुरोध किया कि वे जांच परिणामों पर अपने विचार, यदि कोई हों, इस पत्र की तारीख से 40 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

(च) प्राधिकारी ने 17 सितम्बर, 2002 को सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक रूप से विचार प्रकट कर चुकी सभी हितबद्ध पार्टियों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में प्रस्तुत करें। पार्टियों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां ले लें तथा उस पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, पेश कर सकते हैं। याचिकाकर्ता, निर्यातक तथा उपयोक्ता उद्योग के सदस्य मौखिक सुनवाई में उपस्थित हुए थे।

(छ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को सार्वजनिक फाइल उपलब्ध करवाई जिसमें विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क तथा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय रूप रखे गए थे।

(ज) याचिकाकर्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक जांच परिणामों तथा/या इन जांच परिणामों में उचित कार्यवाही की गई है।

(झ) ऊपर उल्लिखित नियम 16 के अनुसार, इन जांच परिणामों के लिए विचारित तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकट किया गया तथा उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में विचार किया गया है।

(ञ) जांच 01 अप्रैल, 2001 से 31 दिसम्बर, 2002 (9 माह) की अवधि के लिए की गई थी।

(ट) इस अधिसूचना में *** से हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अधीन उसे प्राधिकारी द्वारा गोपनीय ही माना गया है।

ख. जांच में शामिल विभिन्न मुद्दे और प्राधिकारी द्वारा जांच**विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु****आयातकों और निर्यातकों के विचार****मैसर्स केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०, मितसुई एंड कं० तथा अन्य के विचार**

1. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फिनोल है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फिनोल तथा संबद्ध देशों से आयातित फिनोल समान वस्तुएं हैं। तथापि, यह निवेदन किया जाता है कि हमने 99.99 % की प्ररूपी शुद्धता वाले सर्वश्रेष्ठ फिनोल का निर्यात किया था, जिसका याचिकाकर्ता उद्योग उत्पादन करने में सक्षम नहीं था। इस उच्च शुद्धता वाली सामग्री की आवश्यकता आटोमोबाइल उद्योग के विशेष रेजिन तथा भेषज जैसे विकसित प्रयोगों में होती है। जांचाधीन उत्पाद की व्यापक अर्थों में परिभाषित करके उत्पाद को सुरक्षा देने की मांग की जाती है, जिसका विनिर्माण देश में नहीं होता है। यह सुझाव दिया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनी की उत्पादन क्षमता का उचित रूप से सत्यापन किया जाए तथा तदनुसार जांचाधीन उत्पाद में संशोधन किया जाए।

मैसर्स एसओ सी इस स्थिति में नहीं है कि बी पी ए के विनिर्माण के लिए अपेक्षित ग्रेड का फिनाइल दे सके जो पॉलीकार्बोनेट के विनिर्माण तथा विशेष ऐपॉक्सिज के लिए अपेक्षित होता है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लि० मुंबई ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में अपनी टिप्पणियों को दोहराया है और यह साबित किया है कि पॉलीकार्बोनेट ग्रेड बी पी ए के विनिर्माण के लिए अपेक्षित फिनोल समान वस्तु नहीं है।

घरेलू उद्योग के विचार

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फिनोल है जिसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फिनोल मूलभूत कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका विपणन दो ग्रेडों -क्रिस्टेलिन तथा हाइड्रोटाइड और दो रूपों - खुले/बल्क एवं पैकड में किया जाता है।

भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित फिनोल तथा संबद्ध देशों से निर्यातित फिनोल में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित फिनोल संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित फिनोल से भौतिक तथा

रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी (जिसका संबद्ध देशों के अधिकांश उत्पादकों द्वारा अनुसरण किया जाता है), कार्य तथा प्रयोग, उत्पाद विशिष्टिकरण, कीमत, वितरण तथा विपणन एवं वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। दोनों का तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। उपभोक्ता दोनों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाटनरोधी नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित फिनोल तथा संबद्ध देशों से आयातित फिनोल के समान वस्तु है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए शुद्धता और पोलिकार्वोनेट ग्रेड के मुद्दे के बारे में याचिकाकर्ता ने यह पुनरावृत्ति की है कि वह 99.9% शुद्धता के फिनोल का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फिनोल को विस्फिनोल ए पोली कार्वोनेट ग्रेड के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फिनोल है। फिनोल मूलभूत कार्बनिक रसायन है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय XXIX के उपशीर्ष 2907.11 तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय XXVII के उपशीर्ष 2707.60 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का आयात किए जाने वाले वर्गीकरण पर विचार किए बिना ही उसके बारे में वर्तमान जांच की जा रही है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के क्षेत्र किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तु का तात्पर्य उस वस्तु से है जो हर दृष्टि से जांचाधीन उत्पाद के समरूप एवं समान है तथा ऐसी वस्तु के अभाव में दूसरी ऐसी वस्तु से है जिसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती-जुलती हैं।

इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित फिनोल यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर से निर्यातित फिनोल के समान वस्तु है, प्राधिकारी द्वारा उसकी विशेषताओं जैसे कि तकनीकी विनिर्देशन उत्पादन प्रक्रिया, कार्य तथा प्रयोग एवं टैरिफ वर्गीकरण पर विचार किया गया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा विनिर्मित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के समक्ष समान वस्तु है। हालांकि, कुछ निर्यातकों तथा आयातकों ने यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा आयातित फिनोल की गुणवत्ता अलग है। किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस बात की सूचना मिलती हो कि आयातित फिनोल तकनीकी या वाणिज्यिक किसी भी रूप में घरेलू रूप से उत्पादित फिनोल का प्रतिस्थापन नहीं करती है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि विस्पेनॉल ए के एकमात्र निर्माता अपनी फिनोल की आवश्यकता को याचिकाकर्ता से पूरी करते हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फिनोल में वे सब विशेषताएं हैं जो कि संबद्ध देशों से आयातित फिनोल में पाई जाती है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से निर्यातित फिनोल नियमों के अर्थ के अंतर्गत समान वस्तुएं हैं।

जांचाधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में प्राधिकारी अनंतिम जांच परिणामों की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

जांच की शुरुआत, स्थिति तथा घरेलू उद्योग

4. मैसर्स मेरीसोल, दक्षिण अफ्रीका, मितसुई एंड कं०, सिंगापुर, मैसर्स अतुल लि०, मै० फोसेको, मैसर्स एफएमए, मुम्बई, मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि., मुंबई।

1. सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क) नियमावली 1995 (नियमावली) के नियम 5(3) के तहत माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह कोई भी जांच तब तक शुरु न करें जब तक कि वह आवेदन में दिए गए साक्ष्यों की यथार्थता और पर्याप्तता की जांच न कर लें और स्वयं को इस बात से संतुष्ट न कर लें कि निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य हैं :-

(i) पाटन

(ii) क्षति, जहां लागू हो, और

(iii) जहां लागू हो, जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसे पाटित आयातों और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध।

हालांकि याचिकाकर्ता उक्त परीक्षण के भाग (ख) की शर्त को पूरा कर सकते हैं तथापि उक्त परीक्षण के भाग (क) के सत्यापन करने के भार निर्दिष्ट प्राधिकारी पर होता है और ऐसा किए जाने तक अनुरोध है कि इस जांच की शुरुआत को अधिकारातीत और गैर कानूनी माना जाए।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता अर्थात् हिंदुस्तान कौमिकल आर्गेनिक लि० (एच ओ सी एल) ने माना है कि घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा 46.11 % है। चूंकि जांच की शुरुआत के समय माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी याचिकाकर्ता की याचिका दायर करने की यथार्थता और पर्याप्तता का

सत्यापन करने में विफल रहे हैं इसलिए पाटनरोधी नियमों के तहत जांच की शुरुआत करना गैर-कानूनी तथ कानूनन दोषपूर्ण है ।

माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए अपेक्षित दो भागों वाले परीक्षण को पूरा किए बिना ही इस जांच की शुरुआत करके गलती की है । याचिकाकर्ता का घरेलू उद्योग में 25 % से भी अधिक का हिस्सा है, इस बात को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कानूनानुसार माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के अन्य घटकों के मतदान द्वारा आवेदन के समर्थन को सुनिश्चित करना चाहिए ।

15 फरवरी, 2002 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रथम पैरा इस बात की सूचना देता है कि एच ओ सी एल द्वारा याचिका किसी भी घरेलू उद्योग के समर्थन के बिना दायर की गई थी तथा यह घरेलू उद्योग की ओर से नहीं थी । तथापि, प्रारंभिक अधिसूचना के पैरा 2 में किसी भी भाग से किसी पूर्ण समर्थन की अनुपस्थिति के बावजूद प्राधिकारी ने यह रिकार्ड किया कि याचिका के साथ कोई समर्थन प्राधिकारिता न होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स हिंदुस्तान आरगेनिक कैमिकल्ज लि० ने याचिका दायर की है ।

प्रारंभिक जांच परिणामों के ब्योरो से पता चलता है कि प्राधिकारी ने जांच आरंभ करने से पहले याचिका के आधार की प्रयोजनीयता को न तो ठीक से देखा और न ही सत्यापित किया, कुछ विरोधात्मक सूचनाओं पर विचार करते हुए, जिसे कि हम समझते हैं कि यह नियम 5(3)(ख) के अंतर्गत शर्तों को पूरा नहीं करती जिसके अनुसार आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का कुल उत्पादन में 50 % से अधिक का हिस्सा होना चाहिए । याचिकाकर्ता स्वयं ही यह स्वीकार करते हैं कि जांच अवधि के दौरान उनका हिस्सा घरेलू उत्पादन के 50 % से कम बनता है ।

जांच परिणामों में कुछ विरोध है पहले तो यह कहा गया था कि एच सी एल ने याचिका का समर्थन किया था परंतु बाद में ऐसा बताया गया कि एच ओ सी एल घरेलू उद्योग की पात्रता को पूरा नहीं करता इसलिए आधार मानदंड के अनुसार उसे आवेदन करने से वर्जित किया जाता है । जैसा कि ऊपर बताया गया है एच सी एल के समर्थन को सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं करवाया गया था तथा पाटन के कारण एचसीएल का अपवर्जन ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार के आयात घरेलू बाजार के लिए नहीं थे । इसलिए, केवल इसी आधार पर इस जांच को प्रारंभ करना निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करती तथा इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि. ने अपने इस रुख को पुनः दोहराया है कि अनुच्छेद 5(3)(ख) के अधीन शर्त पूरी नहीं हुई है और पाटनरोधी शुल्क के साथ रक्षोपाय शुल्क से दोहरा संरक्षण मिलेगा। मै. मेरीसोल आर एस ए, मै. मेरीसोल आर एस ए (पी टी वाइ) दक्षिण अफ्रीका ने प्राधिकारी द्वारा गलत तरीके से जांच की शुरुआत करने के बारे में अपने पहले के निवेदन को दोहराया है क्योंकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(क) और 5(3)(ख) के अंतर्गत जुड़वां परीक्षणों का सत्यापन करने में विफल रहे हैं। मै. मितसुई एंड कंपनी ने भी यह निवेदन किया है कि स्थिति के बारे में उनके निवेदनों पर विचार नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स हिंदुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लि० द्वारा याचिका दायर की गई। भारत में संबद्ध वस्तुओं के तीन उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन का 47% का हिस्सा बनता है। तथापि, इन तीन उत्पादकों में से मैसर्स हरदिलिया संबद्ध उत्पाद का आयातक है। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मै. हरदीलिया केमिकल्स लि. को घरेलू उद्योग की योग्यता की परिधि से बाहर रखा है। आगे कंपनी ने याचिका को अपना समर्थन व्यक्त किया है तथा लागत सूचना भी उपलब्ध करवाई है। यदि हरदिलिया को योग्य घरेलू उत्पादकों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है तो याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन में 50 % से अधिक पर नियंत्रण होता। इसके अलावा यदि हरदिलिया को योग्य घरेलू उत्पादक के रूप में शामिल कर लिया जाता है तो याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादन के 50 % से अधिक का समर्थन होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता सभी परिस्थितियों में वांछनीय आधार की आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा नियमावली के अंदर घरेलू उद्योग का गठन करता है।

यहां इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अग्रिम लाइसेंस के तहत जैसा कि पहले भी कंपनी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हरदीलिया द्वारा किए गए सभी आयात केवल फिनोल व्युत्पन्नों के निर्यात के लिए थे।

प्रकटन विवरण के उत्तर में याचिकाकर्ता ने इन मुद्दों के संबंध में अपने पहले वाले निवेदनों को दोहराया है जिनकी संक्षिप्ता की दृष्टि से पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

6. घरेलू उद्योग की ओर से एच ओ सी एल मुंबई द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 47 % का हिस्सा बनता है। बड़ी संख्या में निर्यातकों/आयातकों/उपयोक्ताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के पास आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) का उल्लेख किया है जिसके अनुसार उप-नियम (क) के अंतर्गत दिए गए आवेदन के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी तब तक जांच शुरू नहीं करेगा जब तक कि वह जांच के आधार पर समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के समर्थन या विरोध की डिग्री का निर्धारण नहीं कर लेता तथा यह नहीं जान लेता कि आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से या उसके द्वारा किया गया है। बशर्ते कि यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25 % से कम का हिस्सा बनता हो। उपनियम में यह भी बताया है कि याचिका घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई तभी मानी जाएगी जब इसे ऐसे घरेलू उद्योगों का समर्थन प्राप्त हो जिनका संचयी उत्पादन घरेलू उद्योग के उस भाग जिसका आवेदन के लिए समर्थन अथवा विरोध, जैसा भी हो, व्यक्त करते हुए समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50 % से अधिक का हिस्सा बनता हो।

प्राधिकारी ने इस मामले में आयातकों/उपयोक्ताओं/निर्यातकों द्वारा किए गए दावे तथा रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की है। यह पाया गया है कि देश में मेसर्स हरदिलीया कैमिकल्ज लि0 (एचसीएल) फिनोल का अन्य मुख्य उत्पादक है तथा उसने एच ओ सी एल द्वारा दायर याचिका का समर्थन किया है। हालांकि, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मेसर्स हरदिलीया कैमिकल्ज लि0 ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों/क्षेत्रों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था इसलिए प्राधिकारी ने उन्हें घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र से अलग कर दिया है। मेसर्स हरदिलीया कैमिकल्ज लि0 को छोड़कर, मेसर्स एच ओ सी एल आधार के मानदंड को पूरा करता है।

इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि उपरलिखित नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार के मानदंड की पूर्ति करता है। प्राधिकारी उपरलिखित नियम 2(ख) के अर्थों के अंतर्गत याचिकाकर्ता कंपनी को "घरेलू उद्योग" का दर्जा देने पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

रक्षोपाय, पाटनरोधी तथा दोहरी सुरक्षा

7. मैसर्स मेसोल, दक्षिण अफ्रीका, मितसुई एंड कं० लि०, सिंगापुर, मैसर्स अतुल लि०, मैसर्स फॉर्सेको लि०, मैसर्स केसर पेट्रो, मैसर्स एम पी सी एल, मुम्बई, एफ एम ए मुम्बई, यूरोपीय संघ तथा अन्य के विचार

गैट के अनुच्छेद 19 के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क, जो कि आपातकालीन उपाय हैं, की अनुमति दी जाती है। यह तब लागू किए जाते हैं जब घरेलू उद्योग अचानक बढ़े हुए आयातों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। रक्षोपाय शुल्क लगाने से पहले घरेलू उद्योग अवश्य ही 'गंभीर क्षति' से पीड़ित होना चाहिए। यह गंभीर क्षति अवश्य ही अचानक बढ़े हुए आयातों के कारण हुई होगी।

पाटनरोधी क्षेत्र शुल्क के विपरीत जिसमें प्राधिकारी उंपिंग मार्जिन की पूर्ण सीमा तक के शुल्क की सिफारिश कर सकता है, रक्षोपाय शुल्क क्षेत्र में ऐसी कोई संकल्पना नहीं है, रक्षोपाय क्षेत्र के अंतर्गत आयामें हुई अचानक वृद्धि द्वारा हुई गंभीर क्षति को इंगित करने के लिए अधिकतम शुल्क लगाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ प्रतिसंतुलनकारी शुल्क वे शुल्क हैं जो कि निर्यातक देश में लगाए जाते हैं। जैसे कि पाटनरोधी शुल्कों के मामले में होता है, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क भी विनिर्दिष्ट देश व विनिर्दिष्ट निर्यातक के लिए होते हैं। उपर्युक्त नियम के मद्देनजर यह माना जाता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं चूंकि 'वास्तविक क्षति' की प्रतिपूर्ति पाटन मार्जिन तथा इमदाद मार्जिन के अर्थों में की जा सकती है इसलिए शुल्कों को एक साथ एक ही समय पर लगाना संभव है। हालांकि, रक्षोपाय शुल्कों के मामले में शुल्क लगाने का एकमात्र कारण घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति है। इस बात में सर्वसम्मति है कि 'गंभीर क्षति' 'वास्तविक क्षति' से कहीं अधिक होती है और बाद में शामिल किए जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से अन्तर्निहित है कि आयातों में अचानक हुई वृद्धि से गंभीर क्षति हुई है इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क को लगाने से यह प्रमाणित होता है कि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता जिसमें वास्तविक क्षति और पाटन के बीच कारणात्मक संबंध अपेक्षित होता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि एक ही उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

सदस्य राज्य के घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकीय स्थिति द्वारा होने वाली गंभीर क्षति को पूरा करने के लिए ही रक्षोपाय शुल्क लगाए जाते हैं। यही वजह है कि डब्ल्यू टी ओ समझौते में प्रभावित सदस्य

राज्यों को क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रावधान है। इस यथार्थ कारण के लिए प्रभावित सदस्य राज्य को क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए डब्ल्यू टी ओ करार में व्यवस्था है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि भारत में कानून पाटनरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क दोनों एक साथ लगाने को प्रतिबंधित करता है।

मैसर्स मितसुई एंड कं० ने इस बात की ओर ध्यानाकर्षित किया है कि रक्षोपाय प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति की धारणा के विरुद्ध पाटनरोधी नियमावली में केवल वास्तविक क्षति का प्रावधान है। इसलिए, यदि वास्तविक क्षति को हटाने के लिए पर्याप्त शुल्कों की सिफारिश की गई है तो उसी अधिनियम के अंतर्गत यह कम गंभीर स्थिति है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी मामले में पाटनरोधी जांच तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि उस मामले में जांच की तकरीबन उसी अवधि को ध्यान में रखकर रक्षोपाय शुल्कों की सिफारिश की गई हो।

पाटनरोध के लिए जांच अवधि के दौरान फिनोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 382 अमेरिकी डालर प्रति मी० टन पर ही रही क्योंकि उसी के आधार पर ही फिनोल के लिए एसजीडी सुरक्षा को बढ़ाया गया था। इसलिए एसजीडी के विस्तार को इस आधार पर अनुमोदन दिया गया कि फिनोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 382 डालर प्रति मी० टन पर तब तक कीमतें उसी स्तर पर रहे। इसलिए पाटनरोधी शुल्क के रूप में अतिरिक्त संरक्षण के अनुमोदन में कोई औचित्य नहीं है।

आगे यह भी नोट किया जाए कि जुलाई 2001 से आयातों में अत्यधिक वृद्धि तथा विशेषतः अप्रैल, 2001 से दक्षिण अफ्रीका एवं सिंगापुर से आयातों में वृद्धि के कारण पाटनरोधी शुल्कों को लगाने के लिए दायर वर्तमान याचिका में उल्लिखित आधारों के समान आधार पर ही रक्षोपाय शुल्क लगाए गए थे।

फिनोल पर रक्षोपाय शुल्क लगाते हुए डीजी (रक्षोपाय) ने फिनोल के विनिर्माताओं से प्रतिबद्धता ले ली थी कि वे 6000/मी० टन की लागत कटौती प्राप्त कर लेंगे। इसलिए फिनोल का लाभांश अवश्य ही इतना बढ़ गया होगा कि प्रति वर्ष बचत हो सके चूंकि ऐसी बचत उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं हो सकी थी।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०, मुंबई ने यह निवेदन किया है कि संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य परिकलित करने के लिए एस जी डी पर अवश्य विचार किया जाए। रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क के मुद्दे के संबंध में मै. मेरीसोल आर एस ए ने प्राधिकारी को यह सत्यापित करने के

लिए कहा है कि गंभीर क्षति तथा वास्तविक क्षति की गणना की पद्धतियां समकालिक हैं और हालाँकि क्षति का विश्लेषण अलग अलग अवधियों के लिए किया गया है, विशेषतः इसका बोझ उपभोक्ता पर दो तरफा है क्योंकि शुल्क भावी रूप से प्रभावी हैं। मै. मितसुई एंड कं. ने यह निवेदन किया है कि पाटनरोधी जांच और रक्षोपाय जांच के लिए जांच अवधि एक ही है और प्राधिकारी ने इस मुद्दे का समाधान नहीं किया है कि वास्तविक क्षति की संकल्पना कार्य क्षेत्र में गंभीर क्षति के कार्य क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है। प्रकटन विवरण के उत्तर में यूरोपीय संघ ने यह निवेदन किया है कि सभी पक्षकारों को यह प्रदर्शित करने के लिए ठोस साक्ष्य अवश्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए कि दोहरे संरक्षण को हटा दिया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा विचार

8. यह तर्क दिया जा सकता है कि यह पहला उत्पाद है कि जिसमें रक्षोपाय शुल्क लागू किए गए हैं तथा पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की गई है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं बताया जिसमें यह बताया गया हो कि दोनों शुल्क साथ-साथ नहीं लगाए जा सकते।

प्रतिसंतुलनकारी शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क में ऐसी शर्त है जो दोनों को इकट्ठा लागू करने से रोकती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब पाटनरोधी शुल्क तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के एक साथ न लगा सकने के बारे में विशेष कानूनी प्रावधान है, रक्षोपाय शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क एक साथ न लगाए जाने पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसलिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्क किसी कानूनी आधार के बिना हैं। इसलिए, वास्तव में कहा जाए तो रक्षोपाय शुल्क विनिमय समान क्षति पर पाटनरोधी शुल्क तथा रक्षोपाय एक साथ लगाने की इजाजत नहीं देता।

यह सामान्य ज्ञान का मामला है कि भारतीय निर्यातक अन्य देशों को अपने निर्यात के लिए पाटनरोधी शुल्क तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दोनों से एक साथ पीड़ित हैं। जब अन्य देश दोनों शुल्कों को एक साथ लगा सकते हैं तो यह समझा जाता है कि दोनों शुल्क एक साथ लगाए जा सकते हैं।

उस स्थिति में जिसमें आयात कीमत पहले तो उचित थी परंतु बाद में विभिन्न कारणों की वजह से अनुचित हो गई, यह स्पष्ट करती है कि उत्पाद का पाटन बाद की अवधि में शुरू हुआ है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह पता चलता कि आयात (1999 तथा साक्ष्य तथा उससे पहले) पाटित कीमतों पर थे। तथापि, अब ऐसा सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह पता चलता है

कि आयात अनुचित व पाटित कीमतों पर थे । अब जबकि बाजार स्थिति तथा आयात की तरीका बदल गया है तब यह स्वाभाविक है कि घरेलू उद्योग उपलब्ध अन्य उपायों के हकदार होंगे । दूसरी ओर उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से भी उत्पाद का पाटन हो रहा है । वास्तव में रक्षोपाय शुल्क लगाने से क्षति के उस हिस्से पर नजर रखी जाएगी जो आयात उचित कीमत पर हुए हैं और जब आयात होते हैं पाटनरोधी शुल्क के अनुसार उद्योग को संरक्षण की जरूरत होती है ।

समीक्षा 2 महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को आरंभ की गई । हालांकि, महानिदेशक द्वारा की जाने वाली जांच की अवधि प्राधिकारी द्वारा की जाने ली अवधि को परस्पर व्याप्त करती है, समीक्षा का दायरा विकासशील देशों को रक्षोपाय शुल्कों के विस्तार तक सीमित है (जो कि शुल्क के कार्यक्षेत्र में नहीं है) । इस संबंध में आरंभिक अधिसूचना की समीक्षा 2 निम्न प्रकार से है ।

मामले की जांच की गई है तथा प्रथम दृष्टया लगता है कि उपरोलिखित विकासशील देशों से फिर्नाल के आयात कस्टम सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 78ख के अंतर्गत यथानिर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से समीक्षा कार्रवाई आरंभ करने का निर्णय लिया गया है । समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसे अधिसूचित विकासशील देश इन देशों से फेर्नाल के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के भुगतान से छूट के पात्र हैं । (बल दिया गया है)

प्रकटन विवरण के उत्तर में पहुंच मूल्य की गणना के लिए रक्षोपाय शुल्क शामिल करने के मुद्दे पर घरेलू उद्योग का यह निवेदन है कि हालांकि एक ओर आयातों की पहुंच कीमत में रक्षोपाय शुल्क शामिल किए गए हैं दूसरी ओर इष्टतम बनाने और परिकलन के कारण घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षति कारक कीमतों को कम कर दिया गया है इसलिए इष्टतम उत्पादन लागत की गणना के लिए कोई औचित्य नहीं है । तब उत्पादन की लागत वास्तविक स्तर पर लेनी चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि संबद्ध देशों के मूल की संबद्ध वस्तुओं पर रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रक्षोपाय शुल्क से गंभीर क्षति के मुद्दे का निराकरण हो गया है जो कि उस वास्तविक क्षति का हिस्सा है जिसका निवारण पाटनरोधी शुल्क द्वारा किया जाता है । ये भी तर्क दिए गए हैं कि रक्षोपाय शुल्क के रूप में निवारण प्राप्त करने के पश्चात घरेलू उद्योग किसी भी पाटनरोधी शुल्क द्वारा दोहरा लाभ

नहीं उठा सकता है। आगे यह तर्क भी दिया गया है कि कीमत बचत उपायों, जिन्हें अपनाने की घरेलू उद्योग को आवश्यकता भी थी, को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया। इस मामले में कानून विज्ञान में कमी होने के संबंध में भी तर्क दिए गए हैं। भारतीय निर्यातकों द्वारा दूसरे देशों में किए जाने वाले निर्यातों पर प्रति संतुलनकारी शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क एक साथ लगाए जाने पर भी ध्यानाकर्षण किया गया।

प्राधिकारी ने इस मामले से संबंधित उन मुद्दों की जांच की है जहां पर पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने से पहले रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि वर्तमान जांच से भिन्न थी अतः क्षति निर्धारण समान तथा सहसंबंधित नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी द्वारा यह जांच तथा पुष्टि भी की गई कि वर्ष 2001 में दूसरी समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या इस प्रकार अधिसूचित विकासशील देश, इन देशों से फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के भुगतान से छूट के पात्र है।

जहां तक इस तर्क का संबंध है कि डी जी रक्षोपाय ने गंभीर क्षति समाप्त कर दी है तथा यही वास्तविक क्षति समाप्त करने पर भी लागू होती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की प्रकृति उन निर्यातकों के साथ परिवर्तित हो गई है जो उचित कीमत (रक्षोपाय ड्यूटी) पर भी अनुचित कीमत लगाने जैसे तरीके अपना रहे हैं। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब निर्यातक अपने उत्पादों पर अनुचित कीमतों का सहारा ले रहे हैं तो याचिकाकर्ता को भी पाटन रोधन की सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः याचिकाकर्ता को दी जा रही दोहरी सुरक्षा के संबंध में निर्यातकों/उपयोक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क में कोई सार नहीं है। निर्यातकों/आयातकों/उपयोक्ताओं द्वारा यह दावा किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को दोहरी सुरक्षा मिलेगी दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क, उचित आयातों की तुलना में अनुचित आयातों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है, से होने वाली क्षतियों (गंभीर क्षति) को ध्यान में रख कर लगाए जाते हैं। प्राधिकारी ने इससे संबंधित मुद्दों पर ध्यानापूर्वक विचार किया है तथा नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच का उद्देश्य यह देखना है कि क्या फर्म को जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से अनुचित आयातों के कारण कोई क्षति हो रही है। प्राधिकारी का विचार है कि पाटन रोधन और रक्षोपाय जांचों में क्षति का होना सामान्य है तथा पाटनरोधी और रक्षोपाय शुल्क लगाने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्रमशः

पाटित/अनुचित और उचित आयातों से सीमित समय हेतु सुरक्षा प्रदान करना है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि क्षति मार्जिन का परिकलन करते समय संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के निर्धारण में रक्षोपाय शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा।

जांच की अवधि

मै. फोसेको लि० एफ एम ए, मुंबई तथा अन्यो के विचार

10. यह भी कहा गया है कि जांच की अवधि प्रतिनिधिक नहीं है क्योंकि 9 महीने की कम अवधि होने के अतिरिक्त यह असामान्य अवधि थी क्योंकि एम पी एस एल. का 2,00,000 मी.टन क्षमता का नया संयंत्र लगने तथा कम बाजार मांग के कारण विश्व बाजार में फिनाल की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। फिनाल उद्योग के उत्पादन, बिक्री तैयार उत्पाद के अंतिम स्टॉक और तैयार उत्पाद की कीमतों में परिवर्तन होता रहता है।

याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि फिनोल का पाटन जुलाई, 2001 से आरंभ हुआ है तथा नवम्बर 2001 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यह निवेदन किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने जैसे दीर्घकालिक उपायों पर निर्णय लेने के लिए 5 महीने की अवधि बहुत कम है।

याचिकाकर्ता के विचार

11. एक स्थान पर यह उल्लेख किया गया है कि जांच अवधि के रूप में कोई भी विशेष अवधि निर्धारित करने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकार पर कोई रोक अथवा सीमा नहीं है। उसी पैराग्राफ के अन्य वक्तव्य में उल्लेख किया गया है कि जांच के लिए छः महीने की अवधि बहुमूल्य कम है।

निवेदन किया गया है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं। जब कोई प्रतिबंध नहीं है तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अपने निवेक से जांच अवधि के रूप में किसी अवधि का चयन कर सकता है। इस संबंध में न ही डब्ल्यूटीओ करार में और न ही भारतीय पाटनरोधी नियमावली में कोई प्रतिबंध है।

प्राधिकारी की जांच

12. प्राधिकारी ने जांच अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक की ली है, यह अवधि अभी हाल ही की है जब यह मामला 15 फरवरी 2002 को प्रारंभ किया गया था। तिमाही समाप्त होने के

कारण तथा पूर्व आंकड़े प्राप्त होने की संभावना के कारण इस अवधि का चयन किया गया था । प्राधिकारी ने यह भी पुष्टि की है कि पाटनरोधी जांच के लिए नौ महीने का समय पर्याप्त और औचित्यपूर्ण है क्योंकि तीन तिमाही का भी यही समय है जिसके लिए संगत आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं ।

निर्धारित शुल्क, परिवर्ती शुल्क और मूल्यानुसार शुल्क

मै0 अतुल लि0, मै0 फोस्को लि0, महाराष्ट्र सरकार मुम्बई और एल्टा लैब, एमपीसीएल तथा अन्यो के विचार

13. हमारे आधार पर बिना पूर्वाग्रह कि जांच प्रारंभ करना अनुचित है तथा जांच के आगे की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए, यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लेते हैं तो हम वर्गीकृत पाटनरोधी शुल्क लगाने का सुझाव देते हैं । चूंकि क्षति और पाटन मार्जिन 360 अमेरिकी डालर प्रति एमटी की कीमत के आधार पर आकलित किया गया है अतः हम सीआईएफ कीमतों की उचित स्लैब में पाटनरोधी शुल्क तब तक लगाने का सुझाव देते हैं जब तक क्षति समाप्त नहीं हो जाती तथा तत्पश्चात् कोई भी पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए ।

यदि यह समझा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए तो यह फिनाँल कीमत में वृद्धि पर कम होते शुल्क ढांचे के साथ 360 अमेरिकी डालर की आयात कीमत के आधार पर लगाया जाना चाहिए तथा 450 अमेरिकी डालर के आयात पर "शुन्य" पाटनरोधी शुल्क होना चाहिए जिससे घरेलू उपयोक्ता और घरेलू उद्योग की सुरक्षा हो, क्योंकि घरेलू उद्योग को 360-450 अमेरिकी डालर पीएमटी की फिनाँल कीमत के बीच सुरक्षा की आवश्यकता है ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि0 ने अनुरोध किया है कि यदि इस शुल्क पर विचार किया जाना है तो इसे इस प्रकार जोड़ा जाए कि आयात कीमत के लिए 450 अमेरिकी डालर प्रति मी.टन से अधिक कोई शुल्क न लगाया जाए ।

याचिकाकर्ता के विचार

14. वर्गीकृत शुल्क पर दिए गए तर्क के संबंध में यह निवेदन किया गया है कि शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम होना चाहिए । जब तक मार्जिन में परिवर्तन नहीं होता तब तक शुल्क में संशोधन नहीं किया जा सकता ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

पाटन रोधी शुल्क को पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम होना चाहिए । ग्रेडेड शुल्क का यह अर्थ होगा कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन कम होने की जांच पूरी नहीं होगी ।

मांग एवं पूर्ति, एकाधिकार तथा भारतीय उद्योगों का हित

15. मै0 फिकॉम ऑरगेनिक्स लि0, मुम्बई, केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स मै0 फोस्को, पुणे तथा अन्य के विचार

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने इस तथ्य पर टिप्पणी की है कि पूर्ति और मांग में बहुत अंतर है तथा अपर्याप्त घरेलू देशी निर्माण क्षमता फिनाइल के आयातों का मुख्य कारण है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि मै0 मितसुई सिंगापुर लि0 (एमपीएसएल) ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ एक नया संयंत्र स्थापित किया है जो इसे बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर फिनॉल बेचने का अधिकार देता है। उन्होंने खपत और भारत में दो घरेलू उत्पादकों की संयुक्त उत्पादन क्षमता के बीच निवल कमी पर भी प्रकाश डाला है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. केसर पेट्रोपोडक्स लि0 ने प्राधिकारी का ध्यान फिनोल के प्रयोक्ताओं के लिए प्रतिकूल शुल्क ढांचे और याचिकाकर्ता की अंतर्राष्ट्रीय समस्या के साथ भारतीय बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने वर्तमान मूल्य वृद्धि और आपूर्ति बाधा से संबंधित मुद्दे को पुनः उठाया है। मै. फिकोम आर्गेनिक्स लि0, मै. फिकाम आर्गेनिक्स लि0 मुंबई ने इस तथ्य को उजागर किया है कि बाजार में फिनोल की बहुत कमी है और भारतीय फिनोल निर्माता फिनोल की आपूर्ति की संविदात्मक पूर्तियां करने में कतई सक्षम नहीं हैं। उन्होंने संबद्ध वस्तु की एक वर्ष में 70% से अधिक कीमत वृद्धि की सूचना भी दी है और अनुरोध किया है कि समग्र उद्योग के हित में फिनोल पर से तुरन्त पाटन रोधी शुल्क हटाया जाए।

याचिकाकर्ता के विचार

16. सार्वजनिक हित तथा उपभोक्ता हित को एक दूसरे में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तुओं के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी जो उचित प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक हैं। वास्तव में विशेष रूप से महानिदेशक (रक्षोपाय) का विचार है कि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जन हित में है। जब रक्षोपाय शुल्क, सार्वजनिक हित में था तो इस बात पर तर्क देने का कोई आधार या कारण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं होगा।

यह कहना भी संगत होगा कि जनहित के मुद्दे से संबंधित सभी तर्क नियमों द्वारा समर्थित हैं।

प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग का निवेदन है कि एकाधिकार का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कोई उत्पादक कीमत को नियंत्रित कर सकता है। हम यह दोहराते हैं कि जब एक से अधिक उत्पादक हों तो एकाधिकार नहीं हो सकता और जब कोई उत्पादक कीमत को नियंत्रित करने की स्थिति में हो तो पाटन और क्षति की स्थिति नहीं हो सकती।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि हार्डलिया जिसका सिनेक्टेडि द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, के अतिरिक्त देश में संबद्ध वस्तु का एक मात्र निर्माता है, इसलिए किसी प्रतिस्पर्धा से बचे रहने के लिए उन्होंने वर्तमान याचिका दायर की है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता की कुल क्षमता देश में फिनोल की मांग से कम है और संयंत्र का आकार इतना छोटा है कि इस देश में समग्र मांग को पूरा नहीं कर सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की घटिया

गुणवत्ता के साथ साथ फिनोल के उत्पादन के लिए नियत लागतों को अलग करने, मूल्य ह्रास और उपरी खर्चों के लिए अपनाई गई पद्धति के संबंध में भी मुद्दे उठाए गए हैं।

प्राधिकारी ने उक्त मुद्दों की जांच की है। पाटन रोधी शुल्क का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति का पर्याप्त रूप से निवारण किया जाए। यह तथ्य कि देश में संबद्ध वस्तु का केवल एक ही उत्पादक है (हर्डिलिया जिसे सिनेक्टोडे द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है, अतिरिक्त), से किसी भी प्रकार पाटन रोधी नियमों के अंतर्गत पाटित आयातों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से राहत का दावा करने के घरेलू उद्योग के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता। यह स्वीकृत स्थिति है कि पाटन रोधी शुल्क का स्वरूप और किस्म पाटन की व्यापार विकृतिकारक प्रथा के विरुद्ध निराकरण प्रदान करने की है। इसके अतिरिक्त पाटन रोधी शुल्क से किसी स्रोत से आयातों को प्रतिबंधित करने अथवा रोकने का प्रस्ताव नहीं होता है, इसलिए देश में कुल खपत से घरेलू आपूर्ति कम होने की संगतता नहीं है। इसके अतिरिक्त चूंकि भारतीय औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है, इसलिए उपभोक्ताओं का शोषण करने के लिए एकाधिकार की स्थिति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी की आशंका अनुचित है।

याचिकाकर्ता की आन्तरिक समस्याएं, लम्बे समय तक काम बंदी, कम अंतिम भंडार और अदक्ष उत्पादन

मै0 केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि0 तथा अन्य के विचार

18. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने इस तथ्य पर टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता के उद्योग की आंतरिक समस्याओं के साथ-साथ, अप्रैल-मई, 2001 के दौरान लम्बे समय तक काम का बंद रहना तथा कम अंतिम स्टॉक, घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण हैं न कि पाटित आयात। कुछ हितबद्ध पार्टियों ने भी घरेलू उद्योग के उत्पादन की अक्षम प्रकृति के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने इस तथ्य का भी संदर्भ दिया है कि मई माह के दौरान कम अंतिम स्टॉक के कारण उपयोक्ता उद्योगों को आयात करने पड़े।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि0 ने अपने पहले के निवेदनों को दोहराया है।

याचिकाकर्ता के विचार

19. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि भारतीय निर्माताओं के उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातों के उत्पादन और बिक्री मात्रा के बीच सीधा संबंध है। उपभोक्ताओं द्वारा आयात वस्तु की ओर परिवर्तित होने के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मार्च, 2001 में जांच की अवधि से थोड़ा पहले निर्यातकों द्वारा भारी मात्रा में आयात बुकिंग की गई थी जो अप्रैल तथा उसके पश्चात पहुंचा। इस बुकिंग का प्रभाव याचिकाकर्ता की बिक्री मात्रा तथा तदन्तर उत्पादन पर भी महसूस किया गया। अप्रैल, 2001 में उत्पादन और बिक्री *** तथा *** एमटी तथा *** एमटी के स्टॉक तथा निर्यातकों द्वारा भारी मात्रा में आर्डर बुकिंग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने मई 2001 में संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया। कोई उत्पादन न होते हुए भी घरेलू उद्योग ने आवश्यकता पूरी करना जारी रखा तथा भण्डार सूची को *** एमटी के वास्तविक स्तर तक ले आया। जून, जुलाई और अगस्त में घरेलू उद्योग का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक था। परंतु पाटित वस्तुओं की उपलब्धता के परिणामस्वरूप भण्डार, जो मई में ***

एमटी था अगरत में बढ़कर *** एमटी हो गया । यह उस अवधि के दौरान औसत मासिक बिक्री से अपेक्षाकृत अधिक था । घरेलू उद्योग ने सितम्बर में अपना उत्पाद सीमित कर दिया तथा अपने उत्पाद को कम कीमतों पर बेचने के अथक प्रयास किए जिसके परिणामस्वरूप बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई तथा भण्डार सूची में कमी । अतः कम्पनी ने अक्टूबर में एक बार फिर से अपने उत्पादन में बढ़ोतरी की जो सितम्बर से लगभग दोगुनी थी । परंतु बाजार में भारी मात्रा में फिर पाटित आयातों के कारण बिक्री मात्रा में गिरावट आई तथा उस अवधि के दौरान भण्डार सूची में तकरीबन औसत मासिक बिक्री के स्तर तक वृद्धि हुई । कम्पनी ने नवम्बर में अपना उत्पादन सीमित कर दिया । परंतु इससे कम्पनी को बिक्री मात्रा में वृद्धि न होने के कारण भण्डार सूची में कमी करने में कम्पनी को कोई सहायता नहीं मिली 1 दिसम्बर, 2001 में घरेलू उद्योग का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक था । बिक्री कीमत में कमी करने तथा माल हानि पर बेचने के पश्चात भी कम्पनी माल नहीं बेच पाई जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री मात्रा में कमी और भण्डार सूची में वृद्धि हुई ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में कम अंतिम भंडार के संबंध में घरेलू उद्योग का निवेदन है कि यह विवरण तथ्य से परे है । जांच अवधि के सभी महीनों में घरेलू उद्योग के पास उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार था । कामबंदी के समय भी घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त भंडार था जो कामबंदी की अवधि के दौरान बिक्रियों को पूरा करने के लिए काफी था ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20 प्राधिकारी ने कम्पनी द्वारा दिए गए आंकड़ों पर उनके रिकार्ड सत्यापित किए हैं तथा यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सका था जिसके परिणामस्वरूप बिक्री मात्रा में कमी और भण्डार सूची में वृद्धि हुई ।

वर्तमान कीमत वृद्धि तथा वर्तमान पूर्ति रुकावटों से संबंधित मामला

मै0 फोसेको लि0 और अन्यो के विचार

21. कृपया यह नोट किया जाए कि मितसुई फिनाइल सिंगापुर लि0 द्वारा स्थापित 2,00,000 क्षमता वाले संयंत्र का प्रयोग अब पूर्णतः बीपीए के निर्माण हेतु स्वयं की खपत के लिए किया जा रहा है तथा उन्होंने फिनोल की बिक्री पूर्णतः बंद कर दी है । इस प्रकार जांच की अवधि के दौरान इस संयंत्र द्वारा बिक्री अस्थायी थी जिसकी मामले पर निर्णय लेने के समय अनदेखी की जानी चाहिए ।

यह भी उल्लेख किया गया है कि अभी हाल ही में टेक्सास, अमेरिका में 4 लाख एमटी क्षमता के एल्बामा संयंत्र में भयंकर आग लग गई है जिससे विश्व बाजार में फिनॉल की पूर्ति प्रभावित हुई है ।

याचिकाकर्ता के विचार

22. जांच अवधि के पश्चात के तथ्यों की वर्तमान जांच अवधि से कोई संबंधता नहीं है । बिना पूर्वाग्रह के, मापदण्ड को अलग से नहीं देखा जा सकता । समान महत्व का एक अन्य तथ्य संबद्ध कच्चे माल की कीमतें और उत्पादन लागत पर उनका प्रभाव है । यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जांच अवधि के पश्चात अपरिष्कृत तेल की कीमतें दोगुने से भी अधिक हो गई हैं । संभवतः संगत तथ्य लागत समायोजित

कीमतें और न्यूनतम छः महीने की अवधि है (हालांकि इन हितबद्ध पार्टियों ने तर्क दिया है कि छः महीने की अवधि भी बहुत कम है) याचिकाकर्ता ने नोट किया कि जबकि इन हितबद्ध पार्टियों ने तर्क दिया है कि पाटन छः महीने से अधिक की अवधि का देखा जाना चाहिए, परंतु 1-3 महीने की अवधि की विद्यमान अस्थायी कीमतों जैसे तथ्य वर्तमान जांच में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त हैं।

अन्य मुद्दे

मै0 एचओसीएल, मुम्बई

क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आयातों के पहुँच मूल्य का परिकलन

23. प्रारंभिक जांच परिणामों से पता चलता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आयातों के पहुँच मूल्य के परिकलन के लिए लागू रक्षोपाय शुल्क को भी शामिल किया है। परिकलन, क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया के असंगत है।

डिब्बाबंद फिनाइल पर शुल्क

24. चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डिब्बाबंद और खुली फिनाइल के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित करना उचित समझा है अतः घरेलू उद्योग, डिब्बाबंद फिनाइल में शामिल पैकिंग लागत के संबंध में सूचना देना चाहेंगे। अनुरोध है कि डिब्बाबंद फिनाइल के लिए क्षति रहित कीमत का परिकलन करते समय ऐसी सूचना को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विरोधी हितबद्ध पार्टियों का यह वक्तव्य कि एचओसीएल ही एक मात्र उत्पादक है, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है जिससे विरोधी हितबद्ध पार्टियां भी जानती हैं कि एचओसीएल भारत में फिनॉल के तीन उत्पादकों में से एक है।

याचिकाकर्ता की संस्थापित क्षमता 40,000 एमटी है। रक्षोपाय शुल्क के लिए आवेदन देते समय घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना तैयार की है तथा तदनुसार आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। तदनुसार घरेलू उद्योग की प्रभावी क्षमता 49000 एमटी है।

मै0 सेनेकटेडी हरदीलिया, मुम्बई द्वारा व्यक्त किए गए विचार

25. हमारी कम्पनी भारत में सांश्लेषिक रूट द्वारा फिनाइल के निर्माण में अग्रगामी कम्पनी है तथा इस उत्पाद का निर्माण 1968 से कर रही है। इसके अतिरिक्त पिछले एक दशक से हम कृत्रिम फिनाइल का निर्माण भी कर रहे हैं। हम कृत्रिम फिनाइल का भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं जिसके लिए हमने निशुल्क फिनॉल का आयात किया था। जांच की अवधि के दौरान फिनॉल के हमारे सभी आयात डीईईसी योजना/अग्रिम लाइसेंस के अधीन थे।

संबद्ध देशों से आयातित फिनॉल पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लि0 (एचओसीएल) द्वारा किए गए आवेदन का हम पहले ही समर्थन कर चुके हैं।

हमारे द्वारा प्रदत्त आंकड़े आपके माननीय निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत है। जांच की अवधि के लिए हमारे द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि हमें पाटन के कारण क्षति हुई है।

चूंकि हमारे द्वारा निर्मित फिनाइल व्युत्पत्तियों का अधिकतर भाग निर्यात किया जाता है अतः (घरेलू बाजार में कृत्रिम के निर्माण एवं बिक्री के लिए) हमारे अपने फिनाइल के लिए आबद्ध खपत हमारे घरेलू उत्पादन का बहुत थोड़ा हिस्सा है।

हमारी कम्पनी को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार हमारी कम्पनी को उपर्युक्त जांच के उद्देश्य हेतु घरेलू उद्योग से अलग किए जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

हमें मालूम हुआ है कि मैसर्स एचओसीएल ने आयातित डिब्बाबंद फिनाइल पर पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि के लिए अनुरोध किया है। हम एचओसीएल के इस अनुरोध का समर्थन करते हैं।

मै0 मेरीसोल एसए दक्षिण अफ्रीका

26. प्रारंभिक जांच परिणामों के पृष्ठ-37 के पैरा 43 पर मेरीसोल द्वारा दायर किए गए आंकड़ों को देखते हुए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया कि "इसलिए प्राधिकारी ने ईयू से संबद्ध वस्तुओं के आयातों और दक्षिण अफ्रीका से सभी बड़ी मात्रा के आयातों के लिए कांदला कस्टम द्वारा प्रदत्त पोत आंकड़ों को ध्यान में रखा है। यह निवेदन किया गया है कि मेरीसोल दक्षिण अफ्रीका से विचाराधीन इस उत्पाद का एकमात्र निर्यातक है। मेरीसोल द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी आंकड़े सत्य तथा पूर्ण हैं तथा इसमें दक्षिण अफ्रीका से सभी ड्रम और बल्क आयात को प्रस्तुत किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि निर्यातक के आंकड़ों को पूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए तथा सभी परिकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क साथ-साथ लगाए जाने हेतु आधार के रूप में पोलिओल का उदाहरण दिया है। हालांकि पिछली घटनाओं से स्पष्ट होता है कि रक्षोपाय शुल्क समाप्त किए जाने के समय कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था।

प्रारंभ में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल मै0 एचओसीएल द्वारा प्रदत्त सूचना पर विश्वास करके भूल की है तथा मै0 हरदीलिय, मुम्बई को घरेलू उद्योग से अलग करके उनके आंकड़ों को अनदेखा किया है। यह नोट किया जाए कि मै0 एचओसीएल एक अक्षम उद्यम है तथा एचओसीएल के द्वारा दिए आंकड़ों के आधार पर सभी क्षति परिकलन से उपभोक्ता उद्योग को बहुत कठिनाई हो रही है।

मै0 मितसुई एण्ड कं0, सिंगापुर

27. प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 35 में, उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली और लाभ एवं हानि से संबंधित सूचना को वर्ष 1998-99 के संदर्भ में सूचीबद्ध किया गया है। इस संबद्ध में हम निवेदन करना चाहते हैं कि जांच की अवधि के आंकड़ों की तुलना वर्ष 1998-99 से नहीं की जा सकती क्योंकि

उचित विश्लेषण के लिए निकटतम पूर्ववर्ती अवधि के साथ तुलना करना आवश्यक होगा नहीं तो इसके प्रतिकूल कारण भी दर्शाए जाए।

मैसर्स अतुल लि० मुम्बई

28. हम यहां यह उल्लेख करना चाहेंगे कि अतुल लि० जो लाल भाई ग्रुप की कम्पनी है तथा जिसकी कुल बिक्री 600 करोड़ रुपए की है एवं इसके विभिन्न क्षेत्रों में विविध लाभ हैं। हमारी एग्रों केमिकल्स डिवीजन भिन्न-भिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उत्पादन करता है (शाकनाशी और फफूँदनाशी) तथा घरेलू तथा निर्यात बाजार की जरूरतें भी पूरी करता है। कीटनाशक उद्योग में फिनाइल का इस्तेमाल करने वाले हम प्रमुख उपयोक्ता हैं तथा फिनाइल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रस्ताव से हम पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा।

प्राधिकारी भाग * ६ के पैरा 8 में इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि एचसीएल देश में अन्य प्रमुख उत्पादक है तथा याचिका का समर्थन किया है। हम निवेदन करते हैं कि यहां पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रतिपादित करने के लिए निष्पक्ष रूप से यही मानदण्ड अपनाए जाने चाहिए तथा प्राधिकारी जांच से अपने बहिष्करण पर पुनः विचार करेंगे।

पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

इससे भारी मात्रा में हानि होगी जिसके परिणाम स्वरूप यूनिट बंद हो सकते हैं।

श्रमिकों में कटौती से श्रमिकों में असंतोष/बेरोजगारी, निर्यात में कमी से देश को मूल्यवान विदेशी विनिमय की हानि

मै० फोसेको

29. हम फाऊंडरी और स्टील उद्योग को विशेष केमिकल आपूर्ति करने के लिए बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक हैं इस स्टील उद्योग में मुख्यतः आटोमोटिव, सामान्य इंजीनियरी, रेल, वाल्व तथा संबद्ध छोटे फाऊंडरी सहायक शामिल हैं जो ऑटो निर्माताओं की जरूरतें पूरी करते हैं। जैसाकि आप जानते हैं उपरोल्लिखित फाऊंडरी की अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी के कारण (अर्थात् आटोमोटिव सामान्य इंजीनियरी, रेल, वाल्व) हमारे उपभोक्ता निवेश लागत में वृद्धि वहन करने में अक्षम है जिसके परिणामस्वरूप मे बढ़ी हुई लागत का विलयन करना पड़ा क्योंकि उसकी वसूली हम अंतिम उपयोक्ता से नहीं कर सकते।

फिनाइल की उच्च कीमतों से फिनाइल उपयोक्ता उद्योग की कार्यात्मक लागत अव्यावहार्य हो गई है जिसके कारण ये यूनिट बंद हो रहे हैं।

यह नोट किया गया है कि फिनाइल की बिक्री कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार में दिए गए समय में फिनाइल की पूर्ति और मांग के परिणाम स्वरूप है न कि पाटन के कारण। यह देखा गया है कि तब से फिनाइल निर्माताओं ने फिनाइल की कीमतों में 4000 रुपए पीएमटी और एसीटोन की कीमतों में भी 3500 रुपए पीएमटी वृद्धि कर दी है जबकि कच्चे माल की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

मै0 केसर पेट्रो

30. हम विसफिनाॅल-ए (बीपीए), जिसकी निर्धारित क्षमता 5000 टीपीए है, के निर्माता हैं। फिनाॅल की हमारी आवश्यकता बीपीए के प्रति 0.966 मटी है। हमे एसीटोन की भी आवश्यकता होती है (0.303 एमटी प्रति एमटीबीपीए) जो फिनाॅल का संयुक्त उत्पाद है। इस प्रकार हम अपने उत्पादन कार्यक्रम के फिनाॅल निर्माताओं पर पूर्णतः निर्भर हैं तथा फिनाॅल और एसीटोन की अपनी आवश्यकता को एचओसी से पूरी कर रहे हैं। हमारे एचओसी के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं तथा डिलीवरी, उत्पादन सूचना भुगतान आदि के रूप में हमें उनसे बहुत ही संतोषजनक सेवा मिलती है।

तथापि यह अनुभव किया गया है कि दोनों फिनाॅल निर्माताओं द्वारा अपनाई गई संयुक्त नीति के अंतर्गत फिनाॅल और एसीटोन दोनों की कीमतें जल्दी-जल्दी बढ़ रही हैं। फिनाॅल की कीमत में 1000 रुपए की वृद्धि के कारण बीपीए की निर्माण लागत 1000 रुपए प्रति एमटी बढ़ जाती है। हम इन बढ़ोतरीयों को उत्पादन लागत में लगाकर अपने उपभोक्ताओं से नहीं ले सकते क्योंकि बीपीए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर उपलब्ध है तथा अपने उपभोक्ताओं को बनाए रखने के लिए हमे इस प्रकार की बढ़ोतरी को आत्मसात करना होगा जिसके परिणाम स्वरूप हम बिना किसी लाभ के काम कर रहे हैं।

मै0 फिकाॅम आरगेनिक्स

31. हम वर्ष 1983 से 1998 तक भारत में अल्काईल फिनाॅल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक थे तथा हमारी मै0 हिन्दुस्तान आरगेनिक्स केमिकल्स लि0 कोचीन से फिनाॅल की भारी मात्रा में खपत थी। परंतु व वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अल्काईल फिनाॅल के आयात शुल्क में भारी कमी हुई जो अपने मूल स्तर 100% से 30% हो गई, जिससे पास के देशों से भारत में अल्काईल फिनाॅल के सस्ते आयात का मार्ग खुल गया। हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके क्योंकि हमारे लिए कोई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सुरक्षा नहीं थी और न ही फिनाॅल कीमत पर कोई नियंत्रण था क्योंकि फिनाॅल के केवल दो निर्माता थे।

हम संयंत्र की पूरी क्षमता का भी प्रयोग नहीं कर सके क्योंकि एचओसीएल से फिनाॅल की पूर्ति अनियमित थी।

जब भारतीय निर्माता घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकते तो फिनाॅल के उपभोक्ता के समक्ष आयात के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है और यदि ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता तो विशेष रूप से हमारे जैसे निर्माताओं को अपने तैयार माल की उच्च लागत के कारण अपने संयंत्र बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

इस समय अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तकरीबन 750/एमटी अमेरिकी डालर निर्धारित की गई हैं। स्थानीय सीमाशुल्क, रक्षोपायशुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क और भण्डारण लागत के साथ इतनी अधिक कीमत होने पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का हमे कोई औचित्य नहीं दिखता क्योंकि इससे फिनाॅल के उन उपभोक्ताओं पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा जो घरेलू निर्माताओं से उपलब्ध न होने के कारण आयात करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसी स्थिति में भारत में फिनाॅल का पाटन संभव नहीं है।

ऐसी स्थिति में हमारा आपसे यह भी अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क को भारत में उत्पादित किए जा रहे एल्काईल फिनोंल की सभी श्रेणियों पर लागू किया जाए क्योंकि हमें सस्ते आयातों के विरुद्ध अन्य देशों से भी समान सुरक्षा की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र सरकार, ऊर्जा विभाग

32. महाराष्ट्र में फिनोंल पर आधारित अनुप्रवाह उत्पादों के निर्माताओं से इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस प्रकार के शुल्क लगाना उनके लिए अत्यधिक हानिकारक होंगे तथा उनमें से कई को अपना उत्पादन या तो बंद करना पड़ सकता है या अपने उत्पादन में भारी मात्रा में कमी करनी पड़ेगी क्योंकि वे पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण अपने उत्पादों को उत्पादन लागत से कम पर बेच रहे हैं।

अनुरोध है कि फिनाल निर्माताओं और फिनोंल उपयोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए जिसकी फिनोंल और फिनोंल आधारित उद्योग की दीर्घकालिक वृद्धि के लिए भी आवश्यकता है।

मै0 एमपीसीएल

33. इस पर ध्यान दिया जाये कि याचिकाकर्ता की तरह फिनोंल उपयोक्ता भी घरेलू उद्योग हैं, जिन्हें ऐसी बाजार परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें उनका अस्तित्व बना रहे। अतः इस बात पर विचार किया जाना है कि न केवल उन याचिकाकर्ताओं के हित की रक्षा की जाए जिनकी वित्तीय स्थिति याचिकाकर्ता उत्पाद के अनुप्रवाह छोटे और मध्यम क्षेत्र के उपयोक्ताओं से अच्छी है अपितु किस प्रकार सम्पूर्ण घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा की जाए।

अन्य मुद्दे:- मै0 प्रगति केमिकल्स द्वारा व्यक्त किए गए विचार

34. उन्होंने फिनोंल संयंत्र की उच्च लाभप्रदता की ओर तथा इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया है कि एचओसी पहले फिनोंल का आयातक था। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ताओं की तरह फिनोंल उपयोक्ता भी घरेलू उद्योग हैं जिन्हें बाजार परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बनाए रखना आवश्यक है।

अन्य मुद्दे:- एल्टा लेबोरेट्रीज द्वारा व्यक्त किए गए विचार

35. हम बल्क ड्रग्स और फाइन केमिकल्स मुख्यतः सेलीसाईक्ल एसिड तथा इसके कृत्रिम के निर्माता हैं तथा फिनोंल हमारी मूल कच्ची सामग्री है। वर्ष 1987 से पहले मै0 हरदीलिया केमिकल्स लि0 फिनोंल के एकमात्र निर्माता थे तथा हमें उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा था जो एकाधिकार पूर्तिकर्ता में निहित होती है। मै0 हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लि0 के आगमन से हमें आशा थी कि स्थिति में सुधार होगा परंतु यह केवल भ्रम था।

याचिकाकर्ता की तरह हम भी घरेलू उद्योग हैं तथा हमें भी ऐसी बाजार परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें हमारा अस्तित्व बना रहें। हमारा मुख्य उत्पाद एस्पीरिन डीपीसीओ के अंतर्गत संविधिक कीमत नियंत्रण के अधीन है तथा सरकार हमसे इस दवाई को उचित कीमत पर बेचने की अपेक्षा रखती है। एस्पीरिन का हमारी कुल बिक्री में 60% से अधिक का हिस्सा है। अतः इस पर विचार किया जाना है कि केवल याचिकाकर्ता के हित को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण घरेलू उद्योग के हित की कैसे रक्षा की जाए।

अन्य मुद्दे: अखिल भारतीय उद्योग संघ द्वारा व्यक्त किए गए विचार

26. हम आपके ध्यान में यह बात लाना चाहेंगे कि यूरोप, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से आयातित फिनाँल की निवेश लागत में भारी वृद्धि से हमारे एक सदस्य पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है।

विशेष केमिकल की मुख्यतः फाउंडरी और स्टील उद्योग को पूर्ति की जाती है जिसमें प्रमुखतः आटोमोटिव, सामान्य इंजीनियरी, रेलवे वाटव और संबद्ध घरेलू उद्योग सहायक शामिल हैं जो आटो निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

अतः फाउंडरी उद्योग और फाउंडरी केमिकल पूर्तिकर्ता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए तथ हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा है।

यूरोपीय संघ

37. इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ आपका ध्यान सूचना के असंबद्ध उपयोग की ओर दिलाना चाहेगा। यह निर्धारित करते समय कि क्या यूरोपियन संघ से निर्यात न्यूनतम स्तर से कम थे, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआई एण्ड एस से प्रकाशित आंकड़े अपूर्ण होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का उपयोग किया है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस अभिकथन कि आयातों का पहुँच मूल्य, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से बहुत कम पाया गया है सक्षम प्राधिकारी से विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के अंतर्गत यथानिर्धारित क्षति कारक सभी तथ्यों का विश्लेषण किया जाना और अधिक आवश्यक हो गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान पाटनरोधी जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान कीमत वृद्धि, वर्तमान आपूर्ति संबंधी बाधाओं और उठाए गए अन्य मुद्दों के बारे में प्राधिकारी द्वारा जांच

1. प्राधिकारी द्वारा सतत रूप से यह स्वीकार किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, इसके साथ ही साथ प्राधिकारी ने सतत रूप से यह माना है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ताओं की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित नहीं होगी। अन्ततोगत्वा उपयोक्ता उचित कीमतों पर सामग्री की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।
2. ये तर्क दिए गए हैं कि भारतीय उत्पादक संयुक्त रूप से कीमत में वृद्धि करते हैं यदि भारतीय उत्पादक कीमतों में निश्चित सीमा से अधिक वृद्धि करते हैं तो उस पर आयातों के रूप में स्वतः अंकुश लग जाएगा।
3. यह तथ्य कि देश में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक हैं और घरेलू उत्पादकों के इस अधिकार को किसी भी तरह से बाधित नहीं करता है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत पाटित आयातों के विरुद्ध राहत की मांग करें। यह स्वीकार किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क प्रकृति एवं रूप में पाटन के विकृत व्यापार व्यवहार के विरुद्ध उपचार प्रदान करता है। इसके अलावा, पाटन रोधी शुल्क किन्हीं स्रोतों से आयातों को प्रतिबंधित अथवा रोकने का प्रस्ताव नहीं करता है और इसलिए घरेलू आपूर्ति के देश में कुल मांग से कम होने का मुद्दा संगत नहीं है। चूंकि भारतीय उपयोक्ताओं को आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, याचिकाकर्ता कंपनी की उपभोक्ताओं का शोषण करने की एकाधिकारी स्थिति संबंधी कार्यकलापों की आशंका गलत साबित होती है।

4. जहां तक विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तु के अक्षम आपूर्तिकर्ता होने के बारे में उठाए गए मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि उसने उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार करके क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।

ग. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

पाटन मार्जिन से संबंधित मुद्दे

मै0 मितसुई एण्ड कं0, सिंगापुर व अन्यो द्वारा व्यक्त किए गए विचार

38. ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न देशों के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन वास्तविक लागत आंकड़ों पर आधारित नहीं है अपितु ये याचिकाकर्ता द्वारा दी गई परिकलित लागत पर आधारित है। इसमें बहुत भिन्नता है तथा आंकड़ों की उचित जांच करने की आवश्यकता है। जैसाकि प्रारंभिक जांच परिणामों में शामिल किया गया है हम निर्यातक मै0 मितसुई एण्ड कं0 तथा मेरीसोल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करते हैं।

प्राधिकारी ने एम पी एस एल के मामले में निर्यात कीमत के 28.75% तथा मितसुई एंड कं. के लिए निर्यात कीमत के 28.5% का पाटन मार्जिन निकाला है। मेरीसोल, दक्षिण अफ्रीका के मामले में पाटनमार्जिन खुली बिक्रियों के लिए 42.24% तथा ड्रम बिक्रियों के लिए 36.48% परिकलित किया गया है। तथापि यूरोपीय संघ के मामले में यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा यथानिर्धारित परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर पाटन मार्जिन 97.72% लिया गया है। अनुरोध है कि सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ में पाटन मार्जिन में इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता क्योंकि इस अंतर को न्यायोजित ठहराने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया तथा कच्ची सामग्री की लागत में इतना अंतर नहीं होगा।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि0 ने यह अनुरोध किया है कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक प्रतीत होता है और फिनोल के निर्यातक विश्व में प्रमुख प्रतिस्पर्धी होने के कारण यदि इस प्रकार के अवास्तविक पाटन मार्जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा तो घरेलू उपयोक्ता को गंभीर क्षति होगी। पाटन मार्जिन की गणना संबंधी पद्धति के मुद्दे पर एक निर्यातक मै. मेरीसोल, आर एस ए ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह सर्वोत्तम सूचना अर्थात् 6(8) के उपयोग पर पुनः विचार करें क्योंकि निर्यातक के सामने मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने में वाणिज्यिक बाधाएं और चुनौतियां थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक और गलत है, कारकों से क्षति का पता नहीं चलता है और कारणात्मक संबंध की पुष्टि नहीं होती है तथा सिफारिश किया गया शुल्क बेहद अनुचित है। पाटन के मुद्दे पर मै. मितसुई एंड कं. ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि निर्यातक प्रश्नावली से संबंधित विभिन्न परिशिष्ट उनके लिए प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि वे व्यापारिक कंपनी हैं और उनकी उत्पादन लागत के आंकड़े अप्रासंगिक हैं।

याचिकाकर्ता के विचार

39. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों प्रश्नावली के प्रपत्र के साथ साथ जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना भेजी थी। सिंगापुर अथवा दक्षिण अफ्रीका की केवल दो कंपनियों ने तथा सिंगापुर के एक व्यापारी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर दिया है। प्रारंभिक जांच परिणामों में यह स्वीकार किया गया है कि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से पूर्ण उत्तर दायर नहीं किया है और निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा महत्वपूर्ण सूचना रोक ली गई है इस बात को स्वीकार करने के बाद भी कि निर्यातक ने पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, प्रारंभिक जांच परिणामों में आंशिक सूचना स्वीकार की गई है और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है जिसके कारण पाटन मार्जिन कम रहा है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर में कमी उस सूचना के स्वरूप में है जिसे निर्यातकों द्वारा जानबूझ कर रोका गया है। ऐसा मामला होने के कारण आंशिक उत्तर की स्वीकृति निर्यातकों को आंशिक उत्तर प्रदान करने के लिए बोनस देने के अलावा कुछ नहीं है।

40. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निम्नलिखित के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

क. मितसुई एंड कं.

ख. मितसुई फिनाल, सिंगापुर

मितसुई एंड कं. द्वारा दायर उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी द्वारा निर्यातित वस्तु मितसुई फिनाल सिंगापुर द्वारा निर्मित वस्तु थी। यह उत्पादक की पहचान के बारे में प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न के उत्तर में था। इस संबंध में निम्नलिखित बातें प्रासंगिक हैं-

चूंकि मितसुई एंड कं. संबद्ध वस्तु की उत्पादक नहीं है इसीलिए उक्त कंपनी अलग से पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु पात्र नहीं है। आदेशानुसार कंपनी संबंधित उत्पादक के साथ-साथ पाटनरोधी शुल्क की दर पुनर्निर्धारित करने की मांग कर सकती है।

चूंकि मितसुई एंड कं. तथा मितसुई फिनाल सहायक कंपनियां हैं इसलिए मितसुई एंड कं. द्वारा की गई बिक्रियों को अपनी सहायता कं. के जरिए मितसुई फिनाल द्वारा की गई बिक्रियों के रूप में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार मितसुई एंड कं. की ऐसी कोई बिक्री नहीं हुई है जो मितसुई फिनाल ने न की हो। ऐसे मामले में मितसुई एंड कं. द्वारा पृथक पाटन मार्जिन की मांग नहीं की जा सकती।

मितसुई फिनाल द्वारा दायर उत्तर उस सीमा तक अधूरा है जिस सीमा तक कंपनी ने भारत को हुए निर्यातों के तथ्य का खुलासा नहीं किया है जिन्हें वस्तुतः मितसुई एंड कं. द्वारा किया गया था। इस प्रकार भारत को किए गए एक ही निर्यात सौदे पर पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु दो बार विचार किया गया है— एक बार मितसुई कं. के निर्यातों के रूप में और दूसरी बार मितसुई फिनाल के निर्यातों के रूप में।

प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने मै. मितसुई फिनोल सिंगापुर लि० से पाटन के मुद्दे पर अपना यह दृष्टिकोण बरकरार रखा है कि निर्यातक ने कंपनी के लाभ एवं हानि विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं जो कंपनी की उचित उत्पादन लागत के निर्धारण हेतु अत्याधिक महत्वपूर्ण है यह निर्धारित करने के लिए संगत हैं कि क्या निर्यातक देश के घरेलू बाजार में की गई बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई थी। जहां तक मितसुई एंड कं. का संबंध है निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातक को असहयोगी मानने में पूर्णतः न्यायोचित हैं क्योंकि कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है यद्यपि उनका मानना है कि निर्यातक के एक व्यापारी होने के मामले में पृथक पाटन मार्जिन का दावा करने हेतु उक्त निर्यातक के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। जहां तक मै. मैरीसोल का संबंध है चूंकि निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है इसलिए इस बात को समुचित ढंग से माना गया है कि निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी ने धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी। प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों और निर्यातक एसोसिएशन से उत्तर प्राप्त किया

मितसुई एंड कं. सिंगापुर शाखा

मितसुई फेनाल, सिंगापुर लि. (एम पी एस एल), सिंगापुर

मेरीसोल आर एस ए (पी टी वाई) लि. दक्षिण अफ्रीका

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. मितसुई एंड कं. लि० सिंगापुर शाखा जापान में निगमित एवं सूचबद्ध एक सरकारी कंपनी है। जांच अवधि के दौरान उन्होंने भारत में अलग अलग कंपनियों को निर्यात किया है यद्यपि वे कोई घरेलू बिक्री नहीं करते हैं। दूसरी ओर मै. मितसुई फिनाल सिंगापुर (पी टी ई) लि० सिंगापुर ने जांच अवधि के दौरान व्यापार घरानों के जरिए निर्यात किया है और उन्होंने इस अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियां भी की हैं।

सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण

42. सिंगापुर के निर्यातकों में से केवल मै. मितसुई एंड कं. लि० सिंगापुर शाखा और मै. मितसुई फिनाल सिंगापुर लि. ने उत्तर दिया है। मै. मितसुई फिनाल सिंगापुर (पी टी ई) लि० ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है और उन्होंने परिशिष्ट 1 के अनुसार बीजक सं. एवं तारीख के साथ बिक्री की गई मात्रा का ब्यौरा दिया है उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि उन्होंने व्यापार घरानों के जरिए भारत में फिनाल की बिक्री की है और उन्होंने किए गए पोत लदानों के ब्यौरों के साथ ग्राहकों के नाम व पते दिए हैं। तथापि उन्होंने अपने अनुरोधों में पिछले तीन वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण तथा तुलनपत्र संलग्न नहीं किए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक ने प्रश्नावली के अपने उत्तर के अनुसार अपने अनुरोध में परिशिष्ट 8, 9 तथा 10 में यथा अपेक्षित वित्तपोषण तथा ब्याज लागत के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने परिशिष्ट 1 में बीजक संख्या, तारीख, बिक्री की गई मात्रा और प्रति यूनिट दर का उल्लेख करते हुए घरेलू बिक्रियों के बारे में अलग अलग सौदे प्रस्तुत किए हैं। निर्यातक ने परिशिष्ट 3 के संबंध में सूचना भी प्रस्तुत की है जिससे भारत को हुए निर्यात और घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों का पता चलता है। उन्होंने परिशिष्ट 4 और 5 को भी प्रस्तुत किया है जिनसे भारत को निर्यात हेतु बिक्री कीमत संरचना तथा घरेलू बिक्री हेतु बिक्री कीमत संरचना का पता

चलता है। इसके अलावा उन्होंने परिशिष्ट 8 और 9 के अनुसार वित्तपोषण और ब्याज लागत को छोड़कर मुख्य शीर्षों के तहत सूचना प्रस्तुत की है जिससे घरेलू बिक्री हेतु कारखाना कीमत और भारत को निर्यात हेतु बिक्री कीमत का पता चलता है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारित औसत आधार पर घरेलू बिक्री हेतु कारखाना कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में और भारित औसत आधार पर ही भारत को बिक्री हेतु कारखाना कीमत को निर्यात कीमत के रूप में लेते हुए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को स्वीकार किया था जो आगे सत्यापन तथा जांच के अधीन थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने प्राधिकारी द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया है और उन्होंने प्रारंभिक जांच परिणामों के दौरान मांगी गई सूचना तथा प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के बारे में बाद में उन्हें लिखे गए पत्रों का उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी उस निर्यातक को असहयोगी घोषित करते हैं और उन्होंने नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य को परिकलित किया है क्योंकि उन्होंने संगत दस्तावेज प्रारंभिक जांच परिणामों तथा बाद में इन्हें उपलब्ध कराने के लिए उन्हें लिखे गए पत्रों के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए हैं अतः प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़ों को भी उचित प्रमाणीकरण और लागू समायोजनों के साथ स्वीकार किया है। इस निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डालर मी.टन बनता है।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस फर्म ने जांच अवधि के दौरान *** अमेरिकी डालर की दर से भारत को सुबद्ध वस्तु के *** मी.टन का निर्यात किया है और समस्त समायोजन करने के बाद कारखाना कीमत *** अमेरिकी डालर प्रति मी. टन बनती है। प्राधिकारी ने कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालते समय निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुसार विभिन्न समायोजनों की अनुमति दी है। इसमें शामिल हैं- छूट *** अमेरिकी डालर प्रति मी.टन की दर से एफ ओ बी से पूर्व प्रभार *** अमेरिकी डालर की दर से, एफ ओ बी के पश्चात समायोजन *** अमेरिकी डालर की दर से, विदेशी भाड़े और प्रति मी. टन आधार पर विदेशी बीमा के लिए *** अमेरिकी डालर की दर से। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डालर मी.टन और निर्यात कीमत *** अमेरिकी डालर मी.टन निर्धारित की है। तदनुसार पाटन मार्जिन *** अमेरिकी डालर मी.टन अथवा निर्यात कीमत की 70.88% बनता है।

मै. मितसुई एंड कं. सिंगापुर

44. मै. मितसुई एंड कं. लि० सिंगापुर शाखा ने उसी प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं जैसे कि मै. मितसई फेनाल पी टी ई सिंगापुर द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने प्रश्नावली के परिशिष्ट १ के अनुसार कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है तथापि परिशिष्ट के अनुसार उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वे घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं करते हैं। उन्होंने किए गए पोत लदानों के ब्यौरों के साथ ग्राहकों के नाम और पत्तोंका उल्लेख करते हुए भारत को किए गए निर्यातों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारत तथा भारत से भिन्न देशों को निर्यात हेतु बिक्री कीमत ढांचे के बारे में आगे और सूचना प्रस्तुत की है। उन्होंने छूट/कमीशन तथा विदेशी भाड़े के लिए समायोजन करने के बाद भारत को निर्यात हेतु कारखाना स्तर कीमत की गणना भी की है। तथापि परिशिष्ट जू और उससे आगे कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि प्राधिकारी ने आगे सत्यापन और जांच के अधीन रहते हुए प्रारंभिक जांच परिणामों के सीमित परियोजना हेतु निर्यातक के अनुरोधों को स्वीकार किया था। तथापि प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद निर्यातक से प्रारंभिक जांच परिणामों में सूची बद्ध सूचना के साथ साथ जांच से संबंधित विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। किन्तु निर्यातक ने आज की तारीख तक कोई संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है। फर्म ने दावा किया है कि उन्होंने तीसरे देश को निर्यात किया है और उन्होंने जांच अवधि के दौरान तीसरे देश को की गई बिक्रियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फर्म ने खपत की गई कच्ची सामग्री तथा उनके व्यय के ब्यौरों उपयोगिताओं के पूर्ण ब्यौरों परिशिष्ट जू, जू और जू में समायोजनों के निर्धारण के आधार जांच अवधि और उससे पूर्व तीन वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र आदि के बारे में उन्हें २० सितम्बर २००२ को लिखे गए पत्र में सूचीबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः प्राधिकारी नियम ६(८) के अनुसार सर्वोत्तम संभव सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य को परिकलित करने के लिए बाध्य हुए हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने लागू समायोजनों के साथ घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को भी स्वीकार किया है और मितसुई फिनाल सिंगापुर लि० के मामले में उचित प्रमार्णाकरण किया गया है। अतः प्राधिकारी ने मितसुई एंड कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य अमेरिकी डालर प्रति मी.टन निर्धारित किया है। निर्यातकों के आंकड़ों से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि फर्मा ने जांच अवधि के दौरान *** अमेरिकी डालर के कुल मूल्य की संबद्ध वस्तु के *** मी.टन का

भारत को निर्यात किया है तथा छूट/कमीशन तथा विदेशी भाड़े के लिए समायोजन करने के बाद कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत *** अमेरिकी डालर/मी.टन ली गई है। प्राधिकारी ने प्रति मी.टन आधार पर निर्यातक द्वारा किए गए दावे के अनुसार *** अमेरिकी डालर मी.दर से छूट/कमीशन, *** की दर से विदेशी भाड़े, *** मी.दर से समुद्री बीमा की अनुमति दी है। मै. मितसुई एंड कैं. के लिए पाटन मार्जिन *** अमेरिकी डालर प्रति मी.टन अथवा निर्यात कीमत का ६०.५६% बनता है।

सिंगापुर से अन्य आयात

45. अन्य गैर-सहयोगी निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी ने मैसर्स मितसुई एण्ड कम्पनी के मामले में यथानिर्धारित उस सामान्य मूल्य को लिया है, जिसका उल्लेख पिछले पैराग्राफ में किया गया है। निर्यात मूल्य के संबंध में प्राधिकारी ने जांचावधि के दौरान भारत को सिंगापुर से निम्नतम निर्यात मूल्य को गैर सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य के रूप में लिया है। कमीशन, समुद्री भाड़ा और बीमा के लिए समायोजन किए जाने के उपरान्त एक्स-फैक्टरी निर्यात मूल्य निकाला गया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन और गैर-सहयोगी निर्यातकों के लिए **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन निर्धारित किया है। गैर सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्रति मीटरी टन **** अमेरिकी डालर अथवा निर्यात मूल्य का 91.70% बैठता है।

सामान्य मूल्य और मैरीसेल आर०एस०ए०(पी टी वाई) , दक्षिण अफ्रीका के लिए निर्यात मूल्य

46. मैसर्स मेरीसोल आर०एस०ए० (पी०टी०वाई०) , दक्षिण अफ्रीका ने प्रश्नावली के प्रति उत्तर भेजा है लेकिन उन्होंने विभिन्न अनुबंधों के संबंध में अपूर्ण सूचना दी है। परिशिष्ट-I के अनुसार उन्होंने बीजक संख्याओं, बेची गई मात्रा, बिक्री मूल्य और प्रति यूनिट दर का उल्लेख करके उनके घरेलू बाजार में विभिन्न बिक्रियों के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है। उन्होंने दो मुख्य ग्रेडों, 'ड्रम' बिक्री और बल्क बिक्री के संबंध में मात्रा और प्रति यूनिट दर के साथ अपने घरेलू बिक्रियों की बीजक संख्या भी दी है। परिशिष्ट-2 में उन्होंने जांचाधीन अवधि के लिए भारत को फिनोल निर्यातों का एक विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने, बीजक मूल्य, समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन आदि का ब्यौरा देते हुए भारतीय ग्राहकों को बिक्रियों का विवरण देकर इस सूचना को संपोषित किया है। परिशिष्ट-3 में उन्होंने भारत को निर्यात, तीसरे देशों को बिक्री और उनके घरेलू बाजार में बिक्रियों का विवरण दिया है। उन्होंने, भारत को निर्यातों

के लिए बिक्री मूल्य संरचना और उनकी घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री मूल्य संरचना का विवरण देते हुए परिशिष्ट-4 और परिशिष्ट-5 प्रस्तुत किया है। तथापि, उन्होंने अपने अन्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य के बारे में पर्याप्त सूचना नहीं दी है। यद्यपि, उन्होंने अपने 'बल्क' और 'ड्रम' बिक्रियों के संबंध में फैक्टरी लागत और भारत को किए जाने वाले निर्यात से लाभ और अपने घरेलू बाजार का विवरण दिया है, तथापि उन्होंने अपनी वित्त पोषण और ब्याज लागत के बारे में अपेक्षित सूचना नहीं दी है और उन्होंने निवल लाभ को, जिसे उन्होंने परिशिष्ट-8-9 में अपनी एक्स फैक्टरी लागतों में जोड़ा है, प्रस्तुत नहीं किया है।

प्राधिकारी ने, लोक सुनवाई के पश्चात निर्यातकों से कहा था कि वे अतिरिक्त सूचना, विशेषकर कि लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं और उन्होंने निर्यातकों से यह भी कहा था कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों का सत्यापन करवाने के लिए अपनी सहयोग देने के बारे में सूचित करें। लेकिन, निर्यातक ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। निर्यातक को ये सूचनाएं देने के लिए कहा गया था - विचाराधीन उत्पाद के लिए व्ययों के आवंटन का आधार, विभिन्न परिशिष्टों में दावा किए गए समायोजनों का आधार, विचाराधीन अवधि और इससे पहले के तीन वर्षों के लिए लाभ व हानि और तुलनपत्र की प्रतियां, परिशिष्ट- VIII और IX में कर से पहले निवल लाभ/हानि और यूनिट बिक्री मूल्य, आदि। चूंकि निर्यातक ने अपेक्षित आंकड़ें प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः प्राधिकारी को नियम 6(8) के अनुसार और उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य निकालने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस संबंध में प्राधिकारी ने लागू समायोजनों और उचित मापदण्डों के साथ घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को भी स्वीकार किया है। 'बल्क' बिक्री के लिए सामान्य मूल्य, प्रतिमीटरी टन **** अमेरिकी डालर और 'ड्रम' बिक्री के लिये प्रतिमीटरी टन **** अमेरिकी डालर बैठता है। निर्यात मूल्य के निर्धारण के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्यातक ने भारत को संबध वस्तु की 'बल्क' बिक्रियों के लिए प्रति मीटरी टन **** अमेरिकी डालर की दर पर **** अमेरिकी डालर मूल्य पर और 'ड्रम' बिक्रियों लिए प्रतिमीटरी टन **** अमेरिकी डालर की दर पर **** अमेरिकी डालर अमेरिकी डालर मूल्य पर **** मीटरी टन मात्रा का निर्यात किया है। प्रतिमीटरी टन आधार पर 'बल्क' बिक्रियों के लिए **** अमेरिकी डालर की दर पर और ड्रम बिक्रियों के लिए **** अमेरिकी डालर की दर पर अंतर्देशीय मालभाड़े के लिए समायोजन करने के उपरान्त निर्यात मूल्य को एक्स फैक्टरी स्तर पर निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी द्वारा 'ड्रम' फिनोल के मामले में **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन की दर पर पैकेजिंग अनुमत किया गया है। प्रति टन आधार पर बल्क बिक्रियों के लिए **** अमेरिकी डालर की दर पर

स्टोरेज, **** अमेरिकी डालर की दर पर हैंडलिंग, **** अमेरिकी डालर की दर पर अन्य प्रभारों को अनुमत किया गया है। 'बल्क' बिक्रियों के लिए प्रति टन आधार पर **** अमेरिकी डालर की दर पर अंतर्देशीय मालभाड़े, **** अमेरिकी डालर की दर पर हैंडलिंग, **** अमेरिकी डालर की दर पर अन्य प्रभार, **** अमेरिकी डालर की दर पर समुद्री मालभाड़े, । **** अमेरिकी डालर की दर पर विदेशी बीमा, और **** अमेरिकी डालर की दर पर नौवहन प्रभारों को अनुमत किया गया है। इस प्रकार, सभी समायोजन करने के उपरान्त, 'बल्क' बिक्रियों के लिए निर्यात मूल्य **** अमेरिकी डालर और ड्रम बिक्रियों के लिए **** अमेरिकी डालर निकाला गया है।

'बल्क' बिक्रियों के लिए पाटन मार्जिन **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन अथवा 'बल्क' बिक्रियों के निर्यात मूल्य का 74.14% और 'ड्रम' बिक्रियों के लिए पाटन मार्जिन **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन अथवा 'ड्रम' बिक्रियों के निर्यात मूल्य का 74.38% बैठता है।

दक्षिण अफ्रीका से अन्य निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

47. निर्यात मूल्य के संबंध में प्राधिकारी ने जांचावधि के दौरान भारत को दक्षिण अफ्रीका से निम्नतम निर्यात मूल्य को 'बल्क' एवं 'ड्रम' बिक्रियों, दोनों के लिए गैर सहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य के रूप में लिया है। प्राधिकारी ने जैसा कि मैसर्स मेरीसोल पी०टी०वाई०लि० के मामले में किया गया है 'बल्क' बिक्रियों और 'ड्रम' बिक्रियों के लिए सामान्य मूल्य क्रमशः **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन और **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन और गैर सहयोगी निर्यातकों के लिए 'बल्क' बिक्रियों और 'ड्रम' बिक्रियों दोनों के लिए निर्यात मूल्य क्रमशः **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन और ।।।। अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन निर्धारित किया है। 'बल्क' बिक्रियों और 'ड्रम' बिक्रियों के लिए पाटन मार्जिन क्रमशः **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन अथवा निर्यात मूल्य का 146.87% और **** अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन अथवा निर्यात मूल्य का 108.69% बैठता है।

₹ 18.77 रु

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

48. प्राधिकारी ने नोट किया है कि यूरोपीय संघ से किसी भी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है। चूंकि संबंध वस्तु की घरेलू बिक्री की संरचना, यूरोपीय संघ में इसकी लागत और अन्य सूचना, के बारे में

कोई भी जानकारी प्रश्नावली के अनुसार नहीं दी गई है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना पर भरोसा करके कार्रवाई की है। याचिकाकर्ता ने उत्पादन की निकाली गई लागत के आधार पर यूरोपीय संघ के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी पाते हैं कि किसी भी निर्यातक ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी जिससे कि वे घरेलू बिक्री मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकें। प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि निर्धारित फार्म और तरीके में संबंध देशों से निर्यातकों से किसी भी उत्तर की अनुपस्थिति में संबद्ध देशों से निर्यातों के संबंध में उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार उनके पास उपलब्ध हुए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए।

तदनुसार, प्राधिकारी ने लागू समायोजनों के साथ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निकाला है। यूरोपीय संघ के लिए इस प्रकार निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य ।।।। अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन है।

प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ से आयात के संबंध में कांडला पोर्ट कस्टम्स द्वारा भेजी गई सूचना से व्यापारवार आंकड़ों को ध्यान में लिया है क्योंकि यह अधिक मात्रा को दर्शाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ ने 438.00 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन की दर पर 5203737 अमेरिकी डालर मूल्य पर 11878 मीटरी टन का निर्यात किया है और समुद्री भाड़ा, विदेशी बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा के लिए समायोजन करने के उपरान्त निर्यात मूल्य एक्स-फैक्टरी स्तर पर ।।।। अमेरिकी डालर बैठता है।

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रति टन आधार पर उपलब्ध सूचना के अनुसार समुद्री भाड़े के लिए ।।।। अमेरिकी डालर, विदेशी बीमा के लिए ।।।। अमेरिकी डालर, कमीशन के लिए ।।।। अमेरिकी डालर, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़े प्रत्येक के लिए।।।। अमेरिकी डालर का समायोजन किया है। पाटन मार्जिन ।।।। अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन अर्थात् निर्यात मूल्य का 77.87 बैठता है।

कुल संख्या	देश	पाटन मार्जिन %
1.	यूरोपीय संघ	77.88
2.	सिंगापुर मित्सुई एंड कं० मित्सुई फिनोल सिंगापुर लि० अन्य निर्यातक	60.56 70.88 91.70
3	दक्षिण अफ्रीका	

	क. मेरीसोल, आर०एस०ए०	
	1. बल्क बिक्री	74.14
	2. ड्रम बिक्री	75.38
	ख. अन्य	
	1. बल्क बिक्री	146.47
	2. ड्रम बिक्री	108.69

घ. क्षति

क्षति मापदण्डों और लाभदेयता से संबंधित विषय और कारणात्मक संबंध

मैसर्स मेरीसोल, दक्षिण अफ्रीका, एफ०एम०ए०, मैसर्स मित्सुई और कम्पनी, मुंबई, प्रगति कैमीकल्स और अन्य के विचार -

49. प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 33 में प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन, क्षमता उपयोग में कमी आने और सामान सूची में वृद्धि होने के कारण क्षति हुई है। यह परिणाम, जांचाधीन अवधि के आंकड़ों का वार्षिकीकरण के लिए उपयोग में लाये गये त्रुटिजनक सिद्धान्तों पर आधारित है, यह टिप्पणियां भी की गई हैं कि प्राधिकारी द्वारा सभी 15 मापदण्डों की जांच नहीं की गई है।

विभिन्न हितबद्ध पक्षों ने इस तथ्य पर टिप्पणी की है कि एच०ओ०सी०एल० ने ए.एम.०१ के दौरान हर उच्च लाभ अर्जित किया है। यह भी कहा जाता है कि फिनोल के विनिर्माता के पास काफी नकदी है जैसा कि पिछले कुछ वर्षों के उनके वित्तीय परिणामों से देखा जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी टिप्पणी की है कि प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच नहीं की है कि क्षति और निर्यात के लिए घरेलू उद्योग की असफलता के बीच कारणात्मक संबंध है। यह भी इंगित किया गया है कि यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड संयंत्र का ब्याज और मूल्यहास को अलग कर दिया जाता है तो ए.एम.०१ के लिए फिनोल संयंत्र पर लाभ 60.89 करोड़ रुपए होगा।

प्रकटन विवरण के उत्तर में ई यू ने प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य पर आकृष्ट किया है कि डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करारों के अनुच्छेद 7.4 द्वारा यह अपेक्षित है कि कम शुल्क का नियम लागू किया जाए और प्रकटन विवरण में इस आशय का कोई संकेत नहीं है कि ऐसा किया गया है।

घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

50. घरेलू उद्योग ने पहले ही आवेदन प्रोफार्मा में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन पर प्रारंभिक निष्कर्षों पर यथासंगत सीमा तक विचार किया गया है।

नियमों के तहत दिए गए विशिष्ट मापदण्डों जैसे कि अन्य देशों से आयात, मांग में संभावित कमी, निर्यात निष्पादन और प्रौद्योगिकीय कारकों, से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं-

बिक्रियों में प्राकृतिक और संभावित कमी:

क. पिछले वर्ष की तुलना में जांचाधीन अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में कमी आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में देश में कथित अधिक मांग के बावजूद कमी आई है।

लाभ:

ख. अभिरक्षा शुल्क लगाने के बाद, घरेलू उद्योग 2000-01 तक लाभ अर्जित कर रहा था। तथापि, जांचाधीन अवधि की दूसरी तिमाही जो सिंगापुर में शुरू हुए उत्पादन से प्रेरित थी, में संबद्ध देशों से निर्यातकों ने अपने मूल्यों में भारी कमी की। घरेलू उद्योग के पास अपने मूल्यों में कमी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था - यहां तक कि लाभ की स्थिति से हानि के स्तर तक। तिमाही कार्यनिष्पादन का विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की लाभदेयता में जांचावधि के दौरान कमी होती रही।

बाजार अंश

ग. भारत में फिनोल के आयातों में संबद्ध देशों का अंश वर्ष 2000-01 में मात्र 31.485 था और इसमें जांचावधि में काफी बढ़ोत्तरी हुई और यह बढ़कर 79.435 हो गया। भारत में फिनोल की मांग में संबद्ध देशों के अंश में भी काफी वृद्धि हुई और यह 2000-01 के 55 से बढ़कर जांचावधि में 405 से

अधिक हो गई , इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा फिनोल के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में काफी वृद्धि हुई ।

उत्पादकता

घ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के बावजूद भी 98-99 और जांचावधि के बीच कमी आई । उत्पादकता, जो वर्ष 1998-99 में 78.10 थी, जांचावधि में घटकर मात्र 46.19 रह गई ।

निवेशों पर प्रतिफल

ड. विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के निवेश पर प्रतिफल, 2000-01 तक सकारात्मक था । तथापि, यह जांचावधि में नकारात्मक हो गया ।

क्षमता उपयोग

च. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में कमी हुई ।

घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक

मूल्य में कमी करना

51. संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से काफी कम था जिसके कारण भारतीय बाजार में मूल्यों में बहुत कमी आ रही थी । आयातों के कारण मूल्यों में 25S से भी अधिक की कमी हो रही थी । इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा मूल्यों में काफी कम किए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग को दामों में काफी कमी उठानी पड़ रही है ।

मूल्य दमन/दबाव

52. आयातों का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से न केवल कम था अपितु घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और गैर क्षतिकारक मूल्य से भी कम था जिससे भारतीय बाजार में मूल्यों पर गम्भीर रूपसे दबाव पड़ रहा था ।

पाटन के मार्जिन की मात्रा

53. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से न केवल अधिक है, बल्कि काफी ज्यादा भी है । घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव अधिक है ।

नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव

54. नकदी प्रवाह, जो 1998-99 में नकारात्मक था, उसके बाद वर्ष 2000-01 तक सकारात्मक हो गया । तथापि, घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह में, संबद्ध देशों से काफी मात्रा में आयातों के बाद जांचाधीन अवधि में बिगड़ाव आया है ।

सामानसूची

55. घरेलू उद्योग के सामान (स्टाक) में इस सीमा तक वृद्धि हुई है कि घरेलू उद्योग को जांचावधि में दो बार अपने उद्योग को बन्द करना पड़ा ताकि अपने सामानसूची स्तर को कम किया जा सके ।

रोजगार

56. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद 98-99 और जांच अवधि के बीच कमी आई ।

मजदूरी

57. देश में लागू अधिनियमों के कारण घरेलू उद्योग के पास कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ।

संवर्धन

58. घरेलू उद्योग ने निर्धारित लागतों के प्रभाव को कम करने के प्रयासों के रूप में रूकावटों को दूर करके अपनी क्षमता में वृद्धि की है ।

पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

59. घरेलू उद्योग, कुछ समय से अपने उत्पादों के बुरे कार्यनिष्पादन के कारण इस चरण में नई पूंजी जुटाने के बारे में नहीं सोच सकता ।

निर्यातकों की क्षमता

60. यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास अधिशेष क्षमता है । वास्तव में उस नए संयंत्र, जिसने सिंगापुर में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, का मुख्य अभिवृद्धि बाजार निर्यात है । अतः स्वभाविकतौर पर भारत का बृहत बाजार निर्यातकों के लिए काफी लाभप्रद है ।

आयातों की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि

61. संबद्ध देशों से होने वाले आयातों में अचानक बहुत वृद्धि हुई है । इन्होंने एक अल्पावधि में बहुत ही उच्च दर दर्शाई है ।

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि:

62. संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। संबद्ध देशों से निर्यात, भौतिक क्षति का जोखिम पैदा कर रहे थे।

ड. प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

63. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध- रू में दिए गए क्षति निर्धारण के सिद्धान्तों में उल्लेख किया गया है कि:

क. क्षति का निर्धारण में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच निहित होगी (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान प्रकार की वस्तु के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) इस प्रकार के उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामस्वरूप प्रभाव।

ख. पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते हुए कथित प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो अचर पद में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मूल्यों के पाटित आयातों के संबंध में जैसा कि नियम 18 के उपनियम (2) में उद्धृत किया है निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद के मूल्यों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्यों में काफी कमी हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव, अन्यथा, मूल्यों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने के लिए है अथवा मूल्य में अन्यथा होने वाली महत्वपूर्ण वृद्धि को रोकने के लिए है।

घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के आकलन के उद्देश्य के लिये निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया गया है।

बिक्री की मात्रा और मूल्य

प्राधिकारी पाते हैं कि बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में जांचाधीन अवधि में बिक्री की मात्रा एवं बिक्री के मूल्य में कमी हुई है। पिछले वर्ष के ऊपर जांचावधि में ईकाई मूल्य प्राप्ति में भी लगभग 26 प्रतिशत की कमी आई है।

पाटित आयातों की मात्रा और बाजार अंश

देश	यूरोपीय संघ (कांडला पत्तन कस्टम्स)		सिंगापुर (निर्यातकों की सूचना जिसके लिये गोपनीय होने का दावा किया गया)		दक्षिण अफ्रीका (निर्यातकों की सूचना जिसके लिये गोपनीय होने का दावा किया गया)	
वर्ष	मात्रा मीटरी टन	अंश %	मात्रा मीटरी टन	अंश %	मात्रा मीटरी टन	अंश %
2000-2001	****	11.05	****	0.58	****	3.34
जांचाधीन अवधि (9 माह)	****	29.13	****	32.30	****	14.18
जांचाधीन अवधि वार्षिकीकृत	****	29.13	****	32.30	****	14.80

प्राधिकारी ने जांचाधीन अवधि और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संबंध देशों से निर्यात की मात्रा के बारे में सूचना की जांच की है। प्रतिशतता के संदर्भ में संबंध देशों से आयातों का बाजार अंश 1999-2000 में 64.3 प्रतिशत, 2000-01 के दौरान 31.48 प्रतिशत और जांचाधीन अवधि के दौरान 46.23 प्रतिशत था। 2000-01 के पिछले वर्ष के साथ तुलना करने पर जांचावधि के दौरान बाजार में अंश भागीदारी ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचावधि के दौरान संबंध देशों से आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

संबंध देशों से आयातों का बाजार अंश			
वर्ष	संबंध देशों से आयात मीटरी टन	कुल आर्येत	अंश प्रतिशत
1999-2000	18730	29128	64.3
2000-2001	4502	14298	31.48
जांचावधि वार्षिकीकृत	41441	54364	76.2

संबंध देशों से आयातों का बाजार अंश (कुल मांग का प्रतिशत)

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं विचाराधीन उत्पादों के अन्य उत्पादकों की बिक्रियों के प्रति कुल आयातों को जोड़कर देश में कुल मांग का परिकलन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंध देशों से होने वाले आयात, 9 महीने की एक अल्पावधि में कुल मांग का 36 प्रतिशत बाजार अंश अर्जित कर पाएँ।

वर्ष	संबंध देशों से आयात मीटरी टन	कुल मांग	प्रतिशत अंश
1999-2000	18730	98764	22.92
2000-2001	4502	81691	5.51
जांचावधि वार्षिकीकृत	41441	113089	36.6

यह भी जांच की जाती है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में जांचावधि के दौरान 26 प्रतिशत की कमी आई ।

	यूनिट	1998-99	1999-00	2000-01	जांचावधि	जांचावधि वार्षिकीकृत
अधिष्ठापित क्षमता	मीटरी टन	40,000	40,000	40,000	30,000	40,000
प्रभावी क्षमता	मीटरी टन	45000	45000	49000	49000	49000
उत्पादन क्षमता उपयोग	मीटरी टन	40142	39261	39055	21756	29008
	प्रतिशत	89.2	87.25	79.7	59.2	59.2
अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार क्षमता उपयोग	प्रतिशत	100.355	98.1525	97.6375	72.52	72.52
अथशेष	मीटरी टन	2464	2885	1517	1920	1920
अन्तशेष	मीटरी टन	2885	1517	1920	2399	2399
घरेलू बिक्री	मीटरी टन	39956	40325	38633	21288	28384
उत्पादन की	रु. मीटरी	100	103.69	133.47	135.8	135.82

लागत	टन					
बिक्री मूल्य	रु. मीटरी टन	100	94	140	108.3	108.3
लाभ/ हानि	रु. मीटरी टन	100	48	173	-25	-25
कर्मचारी	संख्या में	100	98	97	91	91
उत्पादकता/ रोजगार	मीटरी टन	78.1	77.9	78.27	46.19	46.19
आरओओआई	प्रतिशत	9.23	3.64	20.47	.82	.82
मजदूरी	रु० माह	100	111	115	136	136
ऋण प्रवाह	रु० लाख में	****	****	****	****	****

सूचीबद्ध किये गये आंकड़े

उत्पादन एवं याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग का मुद्दामैसर्स मेरीसोल, दक्षिण अफ्रीका, फोसिको लि०, महाराष्ट्र सरकार, एफ एम ए, और अन्यो के विचार

65. यह एच ओ सी एल के तुलनपत्रों से सार्वजनिक कार्य क्षेत्र की सूचना का मामला है कि स्थापित क्षमता प्रभावी क्षमता से बहुत कम है, जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रभावी क्षमता 45000 से 49000 एम टी पी ए है। तथापि याचिकाकर्ता के निजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित तुलन पत्र और सूचना से स्पष्ट है कि स्थापित क्षमता 40000 एम टी पी ए है। उपर्युक्त को देखते हुए याचिकाकर्ता को अपने दावे का ठोस प्रभाव प्रस्तुत करना चाहिए। यह अनुरोध है कि भारत सरकार तथा लेखा परीक्षकों की सूचना को स्वीकार किया जाए और क्षति संबंधी परिमापकों की पुर्नगणना इन आकड़ों का प्रयोग करते हुए की जाए।

इसके प्रकाशित तुलन पत्र के अनुसार एच ओ सी के फीनोल संयंत्र की निर्धारित क्षमता 40000 टी पीए है। अपनी निर्धारित क्षमता के आधार एच ओ सी अत्यधिक क्षमता का उपयोग कर रहा है।

याचिकाकर्ता के विचार

66. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता 40000 मी.टन थी। कंपनी द्वारा कार्यान्वित की गई पुनः संरचनात्मक क्षमता में कारगर ढंग से 49000 मी.टन की वृद्धि की है। इसलिए अब कंपनी की वास्तविक क्षमता 49000 मी.टन है वार्षिक रिपोर्टों और विनिवेश प्रस्ताव में उल्लिखित क्षमता के बारे में कृपया यह नोट किया जाए कि उसमें उल्लिखित क्षमता 40,000 मी.टन स्थापित क्षमता है जबकि पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए संगत क्षमता प्रभावी क्षमता (जो 49,000 मी.टन) है। यह निवेदन है कि स्थापित क्षमता और प्रभावी क्षमता जरूरी नहीं है कि एक समान हो। स्थापित क्षमता का तात्पर्य अधिकांशतः कंपनी द्वारा स्थापित क्षमता से है जबकि प्रभावी क्षमता का संदर्भ उस अधिकतम संभव उत्पादनों से है जिस कंपनी प्रभावी ढंग से कर सकती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

67. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की स्थापित क्षमता के आधार पर क्षमता उपयोग को पुनः परिकलित करने के बारे में हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न निवेदनों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने

याचिकाकर्ता के इस तर्क पर भी विचार किया है कि अड़चनों को दूर करने के बाद उनकी प्रभावी क्षमता में वृद्धि हुई है और अब वह स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने की स्थिति में हैं। प्राधिकारी ने अब उनकी स्थापित क्षमता के साथ साथ कारगर क्षमता के आधार पर घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग का परिकलन किया है और उनका निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में जांच अवधि के दौरान अधिक विकृति आई है।

68 कीमत कटौती और कीमत ह्रास

जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती			
देश	निवल बिक्री कीमत याचिकाकर्ता	संबद्ध देश से पहुंच कीमत	कीमत कटौती
ई यू	****	****	****
एम पी एस आई, सिंगापुर	****	****	****
मितसुई एंड कं., सिंगापुर	****	****	****
मैरीसोल, बल्क, एस ए	****	****	****
मैरीसोल ड्रम, एस ए	****	****	****

जांच अवधि के दौरान कीमत से कम कीमत पर बिक्री			
देश	याचिकाकर्ता की क्षति रहित कीमत	संबद्ध देश से पहुंच कीमत	कीमत से कम कीमत पर बिक्री
ई यू	****	****	****
एम पी एस आई, सिंगापुर	****	****	****
मितसुई एंड कं., सिंगापुर	****	****	****
मैरीसोल, बल्क, एस ए	****	****	****

69. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में यह जांच करना आवश्यक समझा गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्य में बहुत अधिक

कटौती की गई है। अथवा क्या ऐसे आयातों का काफी मात्रा में मूल्यों को कम करने में भी अन्य प्रकर से प्रभाव हुआ है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों में पहुंच मूल्य की तुलना निवल बिक्री वसूली के साथ की है और उसे यह मालूम हुआ है कि पाटित आयातों द्वारा कीमत में काफी कटौती की गई है आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से काफी कम पाया गया है।

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे की भी जांच की है कि घरेलू उद्योग को इस कारण से घाटे हो रहे हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति के मूल्यांकन के लिए कम मूल्य पर बिक्री एवं महत्वपूर्ण सूचक है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए गैर क्षति कारक कीमत की परिकलन किया है और इसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की गणना के लिए पहुंच मूल्य के साथ की है। विश्लेषणों से कम कीमत पर बिक्री करने का पर्याप्त मामला मालूम होता है जिसके कारण घरेलू मामलों को क्षति हुई है। आयातों का घरेलू बाजार में कीमतों को काफी कम करने उनका हास करने का प्रभाव हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों की दृष्टि से अपनी बिक्री कीमत नहीं बढ़ा सका है।

बिक्री कीमत/लाभकारिता

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें उस कीमत से काफी कम है जिससे घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन की लागत की उचित वसूली की अनुमति मिलती और उचित लाभ होता। इस प्रकार पाटित आयातों से घरेलू उद्योग एक उचित कीमत प्राप्त करने के लिए कीमतों में उचित वृद्धि करने से वंचित रहा है। उद्योग को कम बिक्री कीमतों के कारण वास्तविक क्षति हुई है जिनके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत वसूल नहीं हुई। जिनसे वित्तीय घाटे हुए।

प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन क्षति मापदंड इस प्रकार है:-

71. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तरों में जांच अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। जांच अवधि के दौरान समापन भंडारों में बाजार में तेजी आई है जिनसे यह मालूम होता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की भंडार सूची की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है।

कुछ निर्यातकों/प्रयोक्ताओं का यह मत है कि जांच अवधि के दौरान एच सी एल को लाभ हुआ है और एच ओ सी एल को घाटा हुआ है। उन्होंने इस तथ्य पर भी तर्क किया है कि मैसर्स हरडीलिया कैमिकल्स लिमिटेड (एच सी एल) से संबंधित आंकड़ों की भी जांच की जानी चाहिए और उनको पाटनरोधी शुल्क के लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि प्राधिकारी ने उपर्यक्तानुसार घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में एच सी एल का अलग कर दिया है परन्तु उन्होंने एच सी एल द्वारा प्रस्तुत रिकार्डों की जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस निवेदन में कोई सच्चाई नहीं है कि एच सी एल ने जांच अवधि के दौरान लाभ अर्जित किए हैं वस्तुतः उनको **** रूपए का घाटा हुआ है।

माह/वर्ष	उत्पादन की लागत(एच ओ सी एल)रु./मी.टन	निवल बिक्री वसूली(एच ओ सी एल)रु./मी.टन	लाभ/हानि(एच ओ सी एल)रु./मी.टन
1998-99	100	100	100
1999-2000	103	94	48
2000-01	133	140	173
अप्रैल 01-जून-01	135	132	115
जुलाई 01-सितम्बर 01	132	107	-13.5
अक्टूबर 01 दिसम्बर 01	140	87	-170
जांच की अवधि	135	108	-25

वर्ष 1998-99 के सूचीबद्ध आंकड़ों को 100 मानते हुए।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हाइड्रोजन पैंरोक्साइड संयंत्र की लाभकारीता की गणना करने में इसके मूल्य ह्रास को शामिल नहीं किया गया है।

क्षति का संचयी मूल्यांकन

72. अनुबंध-II(iii) के अनुसार ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयातों पर पाटन रोधी जांच की जा रही हो तो प्राधिकारी के लिए ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। जब वह यह निर्धारण करते हैं कि (क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में साबित पाटन मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में 2% से अधिक व्यक्त किया गया हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का प्रत्येक देश से 3% हो और (ख) आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की दृष्टि

से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित हो । प्राधिकारी को यह मालूम हुआ है कि प्रत्येक संबद्ध देश में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी 3% से अधिक है । प्राधिकारी को यह भी मालूम हुआ है कि घरेलू तौर पर उत्पादित समान वस्तु पर संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित है और यह भी मालूम हुआ है कि घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के आयातों द्वारा क्षति का संचयी प्रभाव हुआ है ।

(च) कारणात्मक संबंध

73. यह निर्धारित करने में कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा:-

(क) प्राधिकारी को यह मालूम हुआ कि संबद्ध वस्तु के लिए केवल एक ऐसा बाजार है जहां घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के साथ पाटित आयातों की सीधी प्रतिस्पर्धा होती है । मांग में कमी होना घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कोई कारक नहीं है । आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और समान अनुप्रयोगों/अंतिम उपयोगों के लिए प्रयोग की जाती है । इस प्रकार आयाति स्रोतों अथवा घरेलू स्रोतों से वस्तु की खरीद का निश्चय करने के लिए मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है ।

(ख) संबद्ध देशों से आयातों के कारण भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमतों में उस सीमा तक कटौती हुई और मूल्यह्रास हुआ जिससे घरेलू उद्योग उत्पादन की पूरी लागत वसूल नहीं कर सका और भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित लाभ अर्जित नहीं कर सका ।

(ग) प्राधिकारी ने यह जांच भी की है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है और मांग में कमी, खपत के तरीके में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधक प्रथा और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा तथा प्रौद्योगिकी के विकास के कोई संकेत नहीं पाए गए हैं । उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटित आयातों ने पाटन के प्रभाव के जरिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है ।

(घ) संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य अधिमानी औसत सी आई एफ निर्यात कीमत, सीमा शुल्कों के लागू स्तर (धारा 3, 3(क), 9,9(क) के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) और उतराई प्रभारों के लिए 1% जोड़ने के बाद निर्धारित किया गया है ।

(ड.) घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तु के लिए गैर क्षति कारक कीमत निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की इष्टतम लागत निर्धारित करने के लिए संबद्ध वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत का प्रयोग किया है जिसमें परिकलित सर्वोत्तम खपत मानदंडों और कच्ची सामग्री जिसे जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग किया गया है, की वास्तविक कीमत को ध्यान में रखा गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए उन्होंने जांच अवधि के लिए निर्धारित कारखाना गत गैर क्षति कारक कीमत के साथ आयातित वस्तु के पहुंच मूल्य की तुलना की है।

74. पाटन मार्जिन के समान शुल्क

प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हैं जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी।

(छ) निष्कर्ष

75. प्राधिकारी पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:-

- i) फिनोल अथवा विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है।
- ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- iii) यह क्षति संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।
- iv) प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के समाप्त करने के लिए संबद्ध देशों से फिनोल के सभी आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन उपर्युक्त पैराग्राफों में उल्लिखित हैं। प्राधिकारी पाटन मार्जिन के समान अथवा कम पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं जिसे यदि लगाया जाए तो उससे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की गैर क्षति कारक बिक्री के साथ तुलना करने का प्रस्ताव करते हैं।

तदनुसार प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाएं। पाटन रोधी शुल्क की राशि निम्न तालिक के कालम 3 में उल्लिखित राशि तथा उसके कालम 2 में उल्लिखित देशों के सभी निर्यातकों/विनिर्माताओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 29 और 27 के अंतर्गत आने वाले फिनोल के आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगी:

क्रम संख्या (1)	देश/निर्यातक (2)	राशि (प्रति मी. टन अमरीकी डालर) (3)
1	सिंगापुर क. मितसुई एंड कं.लि. ख. मितसुई फिनोल, सिंगापुर प्रा.लि. ग. अन्य निर्यातक	 710.84 710.84 710.84
2.	दक्षिण अफ्रीका क. मेरीसोल आर एस ए 1. बल्क बिक्री 2. ड्रम बिक्री ख. अन्य निर्यातक 1. बल्क बिक्री 2. ड्रम बिक्री	 710.84 778.59 710.84 778.59
3.	यूरोपीय संघ	710.84

(vi) इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 9 और 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्कों के अतिरिक्त सभी सीमाशुल्कों द्वारा यथा निर्धारित करनिर्धार्य मूल्य होगा।

ज. अतिरिक्त प्रक्रिया

76. उपर्युक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी दिनांक 24 जून 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।
77. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

एल. वी. सप्ताच्छि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2003

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-Dumping investigations concerning import of Phenol originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore.

No. 14/4/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof:

A. PROCEDURE

The procedure described below has been followed with regard to the investigations:

- (a) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Phenol (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from European Union, Singapore and South Africa (hereinafter referred to as subject countries/territories);
- (b) The Authority notified the Embassies/Representative of the subject countries in India about the receipt of petition made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;
- (c) The Authority issued a Public Notice dated 15th February 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Phenol originating in or exported from the subject countries falling under Customs Sub-heading 2907.11 and 2707.60

under chapter 29 and 27 respectively of the Customs Tariff Act, 1975;

- (d) The Authority notified Preliminary Findings vide notification No. 14/4/2002- DGAD dated 24/6/2002 with regard to anti-dumping investigations concerning imports of Phenol originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- (e) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the said findings within forty days from the date of the letter;
- (f) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 17th September 2002. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rejoinders, if any. The petitioners, exporters and members of the user industry were present at the oral hearing.
- (g) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties.
- (h) The arguments raised by the petitioners and other interested parties have been appropriately dealt with in the preliminary findings and/or these findings;
- (i) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same, have been duly considered in these findings;
- (j) Investigations were carried out for the period 1st April 2001 to 31st December 2002 (9 months).
- (k) **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. VARIOUS ISSUES COVERED IN THE INVESTIGATIONS AND EXAMINED BY THE AUTHORITY.

Product under consideration and Like Article

Views of Importers and exporters

Views of M/s Kesar Petroproducts Ltd, Mitsui & Co and Others

1. The product under consideration in this investigation is phenol. The Authority has determined that phenol produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles. However, it is submitted that we exported number one class of phenol with typical purity of 99.99%, which the petitioner industry is not capable of producing. This high purity material is required in advanced applications like pharmaceuticals and special resins for automobile industry. By defining the product under investigation in very broad terms, protection is sought to be extended to products, which are not manufactured in the country. It is suggested that the production capabilities of the petitioner company be suitably verified and the product under consideration be amended accordingly.

M/s HOC is not in a position to give Phenol of the grade required for the manufacture of BPA which goes into manufacture Polycarbonates and is required for special epoxies.

In response to the disclosure, M/s Kesar Petroproducts Ltd, Mumbai, have reiterated their observation regarding product under consideration and like article by maintaining that phenol required for manufacture of Polycarbonate grade BPA is not a like article.

Views of the Domestic Industry

2. The product under consideration in the present petition is Phenol also known as Carboic Acid. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. It is marketed in two grades— Crystalline and Hydrated - and in two forms - loose/bulk and packed.

There is no difference in Phenol produced by the Indian industry and Phenol exported from the subject countries. Phenol produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology (followed by most of the producers from the subject countries), functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Phenol produced by the petitioner and imported from the subject countries are like articles in accordance with the Anti-Dumping Rules.

In response to the disclosure, with regards to issue of purity and polycarbonate grade raised by opposing interested parties, the petitioner reiterates that it produces phenol containing 99.9% purity. Moreover, Phenol produced by the domestic industry can be used in production of Bisphenol-A polycarbonate grade.

Examination By the Authority

3. The Product under consideration in this investigation is Phenol. Phenol is a basic organic chemical classified under Chapter XXIX of Customs Tariff Act under sub heading 2907.11 and subheading 2707.60 under Chapter XXVII of Customs Tariff Act. The present investigations are in respect of the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Custom classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations.

Rule 2(d) of the Anti-dumping Rule specifies that Like articles mean an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

In order to establish that Phenol produced by the domestic industry is a Like Article to that exported from EU, South Africa and Singapore, characteristics such as technical specifications, manufacturing process, functions and uses and tariff classification have been considered by the Authority.

The petitioner claimed that the goods produced by him are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. However, some of the exporters and importers have argued that the phenol imported by them is different in quality. No evidence has been adduced by any of the interested parties to indicate that imported phenol is not substituting the domestically produced phenol either technically or commercially. The Authority notes that the sole producer of Bisphenol A has been sourcing their requirements of phenol from the petitioner. The Authority, therefore, notes that phenol produced by domestic industry has characteristics, which are similar to those of the phenol imported from subject countries. In view of the above the Authority holds that phenol produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles within the meaning of the rules.

The Authority confirms the provisional findings with regards to product under consideration and like article.

Initiation, Standing and Domestic Industry:

4. Views of M/s Merisol, South Africa, Mitsui & Co, Singapore, M/s Atul Ltd, M/s Foseco, M/s FMA, Mumbai, M/s Kesar Petroproducts Ltd, Mumbai

1. Rule 5(3) (b) of the Customs Tariff (Anti Dumping Duty on Dumped Articles), Rules, 1995, ('the Rules') make it incumbent upon the Hon'ble Designated Authority not to initiate an investigation unless it examines the 'accuracy and adequacy of the evidence provided and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding:

- (i) Dumping,
- (ii) Injury, where applicable; and
- (iii) Where applicable, a causal link between such dumped imports and alleged injury, to justify an investigation."

While petitioners may satisfy Part (b) of the test, the onus is on the Hon'ble Designated Authority to verify Part (a) of the test, until such time as is done, it is submitted that this initiation is ultra vires and illegal.

In the instant case, the Petitioner namely Hindustan Chemicals Organic Limited (HOCL) admittedly account for 46.11% of the total production of the Domestic Industry. As the Hon'ble Designated Authority has failed to verify the accuracy and adequacy of the petitioner to file the application, at the time of initiation, therefore, the initiation of the investigation is illegal and bad in law as mandated under the Anti Dumping rules.

The Hon'ble Designated Authority has erred in initiating this investigation without completing the two-part test required for the initiation. Besides, ensuring that the petitioner accounted for over 25% of the domestic industry, the law mandates that the Hon'ble Designated Authority should ascertain the support for the application by 'polling' the remaining constitutes of the domestic industry.

First para of the initiation notification dated 15th February 2002 acknowledges the Petition was lodged by HOCL without any support from any other domestic industry and not on behalf of the Domestic Industry. However, the authority in spite of complete absence of any support from any quarters in para 2 of the initiation notification proceed to record that the Petition has been filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited on behalf of the domestic industry in spite of the fact that no support authorization was also lodged along with the Petition.

The details of preliminary findings reveal that the applicability of standing of the petition has not been adequately dealt with and verified by the Authorities before initiating the investigation, considering certain contradictory information which we feel, does not fulfill the condition under

5(3)(b) wherein the domestic producers expressly supporting the application must account for more than 50% of total production. The petitioners themselves admit that during the period of investigation they accounted for less than 50% of domestic production.

There is contradiction in the findings that it is first stated that HCL has supported the petition and it is then stated that HOCL does not qualify as 'Domestic Industry' and hence excluded for applying the criteria of standing. As stated above HCL support was not available in the public file and excluding HCL due to imports is not correct since such imports were not for domestic market. Thus, on this basis itself, the initiation of this investigation does not satisfy the prescribed criteria and should not be proceeded with further.

In response to disclosure, M/s Kesar petroproducts Ltd have again reiterated their stand that condition under article 5(3)(b) is not satisfied and safeguard duty in combination with Anti Dumping duty would give double protection. M/s Merisol RSA, M/s Merisol RSA (Pty), South Africa has reiterated his earlier submission regarding the incorrect initiation of the investigation by Authority as the it has failed verify the twin tests under 5(3)(a) and 5(3)(b) of the Anti Dumping rules. M/s Mitsui & Co have also submitted that their submissions regarding standing have not taken into consideration.

Views of the Domestic Industry

5. The petition has been filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited on behalf of the domestic industry. There are three producers of subject goods in India. Petitioner accounts for 47% of Indian Production. However, out of three producers, M/s. Herdillia is an importer of product concerned. The Designated Authority has, therefore, excluded M/s Herdillia Chemicals Ltd, from the scope of eligible domestic industry. Furthermore, the company has expressed its support to the petition and has provided its costing information. Should Herdillia be excluded from the eligible domestic producers, the petitioner would command significantly more than 50% of Indian Production. Further, should Herdillia be included as an eligible domestic producer, then petitioner along with support commands more than 50% of Indian Production. The petitioner, therefore, satisfies standing requirement in all the circumstances and constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

It would be worthy to mention here that the all imports made by Herdillia were for exports of Phenol derivatives only, under advance license, as earlier clarified by the company.

In response to the disclosure, Petitioner reiterates its earlier submissions on these issues, which are not being repeated for sake of brevity.

Examination by the Authority

6. The petition has been filed by HOCL, Mumbai on behalf of the domestic industry. The petitioners accounts for almost 47% of the total Indian production of the subject goods. A large number of exporters/importers/users have argued that the petitioners do not have the standing to file the applications. They have quoted 5(3) of the anti dumping rules which says that the DA shall not initiate any investigations pursuant to the application made under sub rule (a) unless it determines on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the domestic industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the domestic industry. It has also been explained in the sub rules that the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing, either support for or opposition as the case may be to the application.

The Authority has examined the contention made by importers/users/exporters in this regard as well as the evidence available on record. It is seen that M/s Herdillia Chemicals Ltd (HCL) is another major producer of Phenol in this country and has supported the petition filed by HOCL. However the Authority notes that Herdillia Chemicals Ltd has imported the subject goods during the POI from the subject countries/territories and therefore the Authority has excluded them from the scope of Domestic Industry. Excluding Herdillia Chemicals Ltd, M/s HOCL satisfies the criteria of standing.

Thus, the Authority holds that the petitioner satisfies the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra. The Authority also proposes to consider this petitioner company as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) supra.

Safeguards, Anti Dumping and Double Protection

7. Views of M/s Meisol, South Africa, Mitsui & Co Ltd, Singapore, M/s Atul Ltd, M/s Foseco Ltd, M/s Kesar Petro, M/s MPCL, Mumbai, FMA, Mumbai, EU and Others

Safeguard duties are an emergency measure permitted pursuant to Article XIX of GATT. It is applied when domestic industry cannot compete with the sudden increase in imports. Prior to the imposition of safeguard duties, the Domestic Industry must be suffering from 'serious injury'. This serious injury must have been caused by the sudden increase of imports.

Unlike in the Anti Dumping sphere, where the Authority may recommend duties to the full extent of the dumping margin, in the Safeguard sphere there is no such concept duties under safeguard sphere can be maximum to address the serious injury by the sudden increase in imports. Countervailing duties on the other hand are duties imposed in the exporting country. Countervailing duties are also country specific and exporter specific, as in the case of Anti Dumping Duties. In view of the jurisprudence above, it is conceivable that both countervailing duties and anti dumping duty may co-exist as the 'material injury' can be compensated in terms of the dumping margin and the subsidy margin, thus, it is possible to have duties simultaneously. However, in the case of safeguard duties, the only measure for imposition of duty is the serious injury to the domestic industry. It is a matter of consensus that the 'serious injury' is far greater than 'material injury' and subsumes the latter. Clearly, it is inherent that there is an admission of serious injury being caused by the sudden increase in imports, thus, warranting the imposition of safeguard duty, there can be no imposition of anti dumping duties which require a causal link between the material injury and the dumping.

In view of the above, it is submitted that there can be no imposition of anti dumping duties and safeguard duties on the same product.

Safeguard duty is primarily protection granted to compensate for 'serious injury' brought about out by the technological state of the domestic industry of the Member state. It is for this precise reason that the WTO agreements provide for the payment of compensation to the affected Member States.

Thus, it is clear that the law in India precludes the imposition of both anti dumping duty/countervailing duty and safeguard duty

M/s Mitsui & Co has pointed out that as against the concept of 'serious injury' to the domestic injury to the domestic industry under the safeguard provisions, the Anti dumping Rules provide only for material injury. Thus, if sufficient duties have been recommended for removing material injury, which under the very same Act is a less serious situation. Thus, it is obvious that an anti dumping investigation cannot be initiated in a case where safeguard duties have been recommended taking into account almost the same period of investigation

The International Price of phenol during the POI for anti dumping has remained at the same at US \$ 382 PMT as the price based on which SGD Protection for phenol was extended. Thus, extension of SGD was sanctioned on the ground that international price of phenol of \$382 PMT and the price remain at the same level. Therefore, there is no justification for sanctioning additional protection in form of anti dumping duty.

It is to be further noted that the grounds on which this safeguard application was made exactly the same as the grounds mentioned in the present petition for imposition of anti dumping duty namely increase in imports from South Africa and Singapore from April 2001 and more particularly major increase in imports from July 2001.

While recommending Safeguard duty on phenol DG (Safeguard) had obtained commitment from phenol manufacturers that they would achieve cost reduction of Rs.6000/MT. Thus, profit of phenol must have gone up to the extent of saving per annum since such saving were not passed on to the customers.

In response to the disclosure, **M/s Kesar Petroproducts Ltd**, Mumbai submits that SGD must be considered for working out the landed value from subject countries. On the Issue of safeguard duty and Anti Dumping Duty, **M/s Merisol RSA**, has asked the Authority to verify that methodologies for calculating serious injury and material injury are synchronized and though the injury analysis is for different periods, practically the burden is on the consumer in two folds as duties are prospective. **M/s Mitsui & Co** has submitted that there is an over lapping of the POI for the Anti Dumping Investigations and safeguard investigations and the Authority has not addressed the issue of as to how the concept of material injury is different in scope than the scope of serious injury. EU, in response to the disclosure has submitted that concrete evidence must be provided to all parties showing that double protection has been avoided.

Views by Domestic Industry

8. It can be argued that this is the first product wherein safeguard duty is in force and anti dumping duty has been recommended. However, there is no legal basis argued by any interested party to state that the two duties cannot run concurrently. Countervailing duty and anti dumping duty have a condition which prohibit simultaneous application of anti dumping duty and countervailing duty. More importantly, even when there is specific legal provision that anti dumping duty and countervailing duties can not be applied simultaneously, there is no legal provision that the safeguard duty and anti dumping duty can not be applied simultaneously. Thus, the entire

argument of the other interested parties is without any legal basis. . . Thus, strictly speaking, the safeguard duty regulation does not provide that anti dumping duty and safeguard duty can not be applied simultaneously against the same injury

It is a matter of common knowledge that Indian Exporters are suffering anti dumping duty and countervailing duties simultaneously against their exports to Other Countries. When other countries can impose the two duties simultaneously, it follows that the two duties can be imposed simultaneously.

In a situation wherein the import price were earlier fair but became unfair subsequently due to various reasons, it is obvious that the dumping of the product starts in subsequent period. In the instant case, there was no evidence that the imports (in 1999 and before) were at dumping prices. However, there is a positive evidence available now that the imports are at unfair and dumped prices. When the market situation and behavior of imports has changed, naturally, the domestic industry would be entitled to another remedy available. To put otherwise, dumping of the product has surfaced with the imposition of safeguard duty on the product. Naturally, the safeguard duty would be taking care of that part of the injury which is due to fairly priced imports and industry requires protection in terms of anti dumping duty when dumping has surfaced.

Review 2 was initiated by the Director General (Safeguards) on 22nd October 2001. Though, the period investigation by the Director General (Safeguards) overlaps with the period being investigated by the Designated Authority, the scope of this review 2 was restricted to extension of safeguard duty to developing countries (which were not in the purview of the duty). The initiation notification of review 2 states as under in this regard.

The matter has been examined and it appears that prima facie the imports of Phenol from the aforementioned developing countries are more than de-minimus level stipulated under section 78B of the Customs Tariff Act 1975 and accordingly it has been decided to initiate review proceedings through this notice. The purpose of the review is to determine whether such notified developing countries are eligible to the exemption from payment of safeguard duty on imports of Phenol from these countries." (Emphasis added).

In response to the disclosure, on the issue of the adding of safeguard duty for the calculation of the landed value, the domestic industry submits that, while on the one hand safeguard duty has been included in the landed price of imports, the non-injurious price has been lowered for the domestic industry on account of optimization and normations. Should the

safeguard duty be included in the calculations, there is then no justification for calculating optimum cost of production. The cost of production should then be taken at actual levels.

Examination by the Authority

9. It has been argued by various interested parties that since the safeguard duty has been imposed on the subject goods originating from the subject countries, there is no need for any Anti-Dumping duty as safeguard duty has addressed the issue of serious injury which is a part of material injury that Anti-Dumping duty addresses. There are also arguments that after having got the redressal by way of safeguard duty, the domestic industry can not have double benefit by the way of anti dumping duty also. It has been further argued that the cost savings measures that the domestic Industry was required to do has not been passed on to consumers. There are also arguments regarding the lack of enough Jurisprudence in this matter. It has also been pointed out that Indian Exporters are suffering anti dumping duty and countervailing duties simultaneously against their exports to Other Countries.

The Authority has examined the issues concerning this case where safeguard duty has been imposed prior to the initiation of anti dumping investigations and concludes that The POI in the safeguard investigation was different than the present investigation and hence the injury determination cannot be assumed to be the same and correlated. It has also been examined and confirmed by the Authority that the purpose of the second review in 2001 was to determine whether such notified developing countries are eligible to the exemption from payment of safeguard duty on imports of Phenol from these countries.

With regard to the argument that the DG, Safeguards has removed serious injury and the same implied removal of material injury also, the Authority notes that the nature of injury has changed with exporters now resorting to unfair pricing from a situation of fair pricing (safeguard duty). The Authority concludes that petitioner now needs the protection of anti dumping when the exporters have resorted to unfair pricing of their products. Hence, there is no merit in the argument raised by exporters/users regarding double protection being accorded to the petitioner. It has been claimed by the exporters and importers/users that imposition of anti dumping duty would amount to double protection to the domestic industry. On the other hand the domestic industry has submitted that the safeguard duty has been imposed on the imports of the subject goods to take into account injuries (serious injury) coming out of fair imports as against unfair imports for which anti dumping duty is required. The authority has carefully considered the issues in this regard and notes

that the purpose of Anti dumping investigations is to examine whether the firm is undergoing any injury due to unfair imports from subject countries during POI. The Authority feels that occurrence of injury is common in anti dumping and safeguard investigations and the imposition of anti dumping and safeguard duty is to grant protection to the domestic industry for a limited timeframe against dumped/unfair and fair imports respectively. The authority concludes that while calculating injury margin, the safeguard duty would be taken into account in determining landed value of subject goods from the subject countries.

Period of Investigation :

Views by M/s Foseco Ltd, FMA, Mumbai and Others

10. It is also stated that the period of investigation is not representative because apart from being a small period of 9 months it was abnormal period since there was major addition to supply of phenol in the world market due to commissioning of MPSL new plant of 2,00,000 MT capacity and depressed market demand. The phenol industry always under goes cyclic variations production, sales, closing stock and prices of finished product.

The petitioner has stated that dumping of phenol started since July 2001 and has submitted statistics up to Nov 2001 only. It is submitted that this period of 5 months is too short a period for taking a decision on long-term measure like imposition of Anti Dumping Duty.

Views of Petitioner

11. At one place, it has been stated that there is no bar or limitations on the power to the Designated Authority to pick any particular period as period of investigation. In the same paragraph, other statement states that six months period is too short for investigation.

We submit that the statement of the opposing interested parties is contradictory. When, there is no bar, the Designated Authority has discretion to choose any period as investigation period. Neither WTO agreement nor Indian Anti Dumping Rules provides any restrictions in this regard.

Examination of the Authority

12. The Authority has taken POI from 1st April 2001 – 31st December 2001 being the most recent period for the investigation when this case was initiated on 15th February 2002. This period was also taken because of the closing of the quarters and the feasibility of getting the complete

data. The Authority confirms that nine months time is adequate and just for Anti Dumping Investigation since it also synchronizes with the three quarters for which the relevant data could be available.

Fixed Duty, Variable Duty and Ad valorem Duty

Views of M/s Atul Ltd, M/s Foseco Ltd, Government of Maharashtra, Mumbai and Alta Labs, MPCL and Others

13. Without prejudice to our stand, that initiation of investigation is improper and further processing of the investigation should be discontinued, we suggest imposition of graded anti dumping duty if the authorities decide to go ahead with the imposition of anti dumping duty. As the calculations of injury and dumping margin are based on a price of US \$ 360/- per MT we suggest imposition of AD duty in suitable slabs of CIF prices till the injury is taken care of beyond which there should not be any levy of anti dumping duty.

If it is still felt that Anti Dumping Duty is to be levied it should be based on import price of US \$ 360 with reducing duty structure on increase in phenol price and at imports of US \$ 450 there should be "zero" Anti Dumping Duty which should protect the domestic consumers and domestic industry, as domestic industry need protection between phenol price of US \$ 360-450 PMT.

In response to the disclosure, M/s Kesar petroproducts Ltd, has requested that if at all such duty is to be considered then it should be linked such that no duty is levied for import price above US\$ 450PMT.

Views of the Petitioner:

14. With regard to the argument on graded duty, it is submitted that the duty has to be lower of dumping margin and injury margin. So long as the margins remains unchanged, the duties cannot be modified.

Examination by the Authority

Anti Dumping duty has to be the lower of the dumping margin and injury margin. Graded duty would imply that the test of lower of the dumping margin and injury margin would not be met.

Demand and Supply, Monopoly and Indian Industries Interest

15. Views of M/s Ficom Organics Ltd, Mumbai, Kesar Petroproducts, M/s Foseco, Pune, and Others

Various interested parties have commented on the fact that there is a large supply and demand gap and there is inadequate domestic indigenous domestic manufacturing capacity which is the major reason for the imports of Phenol. They have also highlighted the fact that M/s Mitsui Singapore Ltd (MPSL) set up a new plant with the latest technology which enabled it to sell phenol at a very competitive price. They have also highlighted on the net shortfall between the consumption and combined production capacity of the two domestic players in India.

In response to the disclosure, **M/s Kesar petroproducts Ltd**, have brought the attention of the Authority towards the demand & supply situation in the Indian market coupled with adverse duty structure for phenol users and internal problem of the petitioner. They have further highlighted the issue regarding the current price increase and supply constraint. **M/s Ficom organics Ltd**, M/s Ficom Organics Ltd, Mumbai, has highlighted the fact that there is an acute shortage of Phenol in the market and Indian Phenol manufacturers are not at all able to fulfill their contractual fulfillments on supply of Phenol. They have also informed of a price hike of more than 70% in a year of the subject goods and have requested that in the interest of the entire Industry, Anti Dumping duty on Phenol be removed with the immediate

Views of the Petitioner:

16. Public interest can not imply consumer interest. Imposition of anti dumping duty would be in public interest as it would help maintaining availability of wider choice to the consumers of subject goods, which is necessary for fair competition. In fact, Director General (Safeguards) has in particular held that imposition of safeguard duty was in the public interest. When safeguard duty was in the public interest, there is no basis or reasoning to argue that imposition of anti dumping duty would not be in the public interest.

It would also be relevant to point out that all the arguments on the issue of public interest are unsupported with the Rules.

In response to the disclosure, the domestic Industry submits that monopoly means a situation in which a producer can dictate the price. We reiterate that when there are more than a producer, there can not be monopoly and when a producer is in a position to dictate the price, there can not be a situation of dumping and injury.

Examination by the Authority

17. It has also been argued by some interested parties that HOCL, is the only producer of the subject goods in the country besides Herdillia which has been taken over by Schenectady and therefore, the present petition

has been filed by them to avoid any competition. Further, the total capacity of the petitioner is short of the demand of Phenol in the country and the size of the plant is too small to cater to total demand of the in this country. It has also been argued that the technology used by the domestic industry is obsolete. Issues have also been raised regarding the poor quality of the goods produced by the domestic industry as well as the methodology adopted for apportionment of fixed costs, depreciation and overheads to the production of Phenol. It has also been stated that the prices of exports to India are at the prices prevailing in international market.

The Authority has examined the above issues. The purpose of anti dumping duty is to ensure that any injury caused to the domestic industry due to dumping is addressed adequately. The fact that there is a single producer of the subject goods in the country (apart from Herdillia which has been taken over by Schenectady) does not, in any way, restrict the right of the domestic producers to claim relief from the Designated Authority against the dumped imports under the Anti Dumping Rules. It has been the accepted position that anti dumping duty is in the nature and form of providing a remedy against the trade distorting practice of dumping. Further, anti dumping duties do not propose to restrict or block imports from any sources and therefore, the issue of the domestic supply being short of the total consumption in the country, has no relevance. Also since alternative sources of supply are available to the Indian industrial users, the apprehension of the petitioner company exercising monopoly position to exploit the customers is misplaced.

Internal problems, long shut down, Low closing stocks and inefficient productions of the Petitioner

Views of M/s Kesar Petroproducts Ltd. and Others

18. Various interested parties have commented upon the fact that internal problems of the petitioner industry coupled with the long shut down period during the April- May 2001 with low closing stocks were the main reason for the injury to the domestic Industry and not the dumped imports. Few interested parties have also mentioned about the inefficient nature of the production of the domestic Industry. They have also referred to the fact that low closing stocks during May month prompted the user industries to go in for the imports.

In response to the disclosure, M/s Kesar Petroproducts Ltd, have reiterated its earlier submissions.

Views of the Petitioner

19. The petitioner has submitted that there is a direct correlation between production and sales volume of the product by the Indian manufacturer and imports from subject countries. Sales volume of the domestic Industry got adversely affected with consumers switching over to imports. In March 2001 i.e. juts prior to the period of the investigation, there was significant import bookings by the exporters, which landed in April and thereafter. Effect of these bookings were felt on the sales volume of the petitioner and consequently upon the production. In April 2001, the production and sales were **** and **** MT and considering the stock level of **** MT as also significant order bookings by the exporters, the domestic Industry decided to take a shutdown in the plant in May 2001. In spite of no production, the domestic industry continue, to meet the requirement and brought the inventory levels to realistic levels of *** MT. In June, July and August, production of the domestic industry was comparatively higher. However, availability of dumped material resulted into significant inventory pile up from *** MT in May to **** MT by August. This was higher than average monthly sales during that period. In September, the domestic industry restricted its production and made hard efforts to sell its produce at reduced prices. This resulted in higher sales volume and reduction in the inventory levels. The Company, therefore, once again increased its production in October, which was almost double than September. However, again due to arrival of significant dumped imports in the market, sales volume remained sluggish and inventories increased to a level of almost average monthly sales during that period. In November, company again restricted its production. However, it did not help the company in reducing inventories significantly as sales volumes did not pick up. In December 2001, production of the domestic industry was comparatively higher. Even after reducing selling price and offering material at loss, the company was not able to sell the material resulting into decline in sales volume and higher inventories.

In response to the disclosure, with regards to the low closing stocks, domestic industry submits that the statement is far away from facts. In all months of the period of investigation, the domestic industry had sufficient stocks to meet the demand of the product. Even at the time of shutdown, the domestic industry had sufficient stocks, which were sufficient to meet sales during the shut down periods.

Examination by the Authority

20. The Authority has verified the records of the company from the data supplied by them and it notes that due to the dumping of the subject goods from the subject countries, the domestic industry was not able to

sell the subject goods resulting into decline in the sales volume and higher inventories.

Issue regarding Current Price Increase and Current Supply constraints

Views of M/s Foseco Ltd and Others

21. It may kindly be noted that plant set up by Mitsui Phenol Singapore Ltd. of 2,00,000 tone capacity is now being used solely for its own captive consumption for manufacturing BPA and they have stopped selling phenol totally. The sale by this plant in POI was thus a temporary event which should be ignored for deciding the matter.

It may also be mentioned that recently there has been a major fire in Albama Plant in Texas, USA of 4 lacs MT capacity, which has affected the supply of phenol in the world market.

Views of the Petitioner:

22. Post period investigation facts have no relevance in the present investigation period. Without prejudice, the parameter can not be seen in isolation. Another factor of equal importance is the prices of associated raw materials and their impact on the cost of production. It would be worthy to mention here that crude oil prices in post investigation period have reached to more than double level. The relevant factor possibly is cost adjusted prices and a minimum period of six months (even though these interested parties have argued that even six months period is too short a period). Petitioner notes that while these interested parties argue that dumping should be seen over a period longer than six months, factors such as present temporary prices over a short period of 1-3 months are arguably sufficient to decide the present investigation.

Other Issues

M/s HOCL, Mumbai

Calculations of Landed Value of imports for determination of injury margin

23. It is found from the preliminary findings that the Designated Authority has included the safeguard duty in force for calculation of landed value of imports. The calculation is inconsistent with the practice being followed for determination of injury margin

Duty on packed phenol

24. Since the Designated Authority has considered it appropriate to determine separate duty for packed and loose phenol, domestic industry would like to provide information with regard to packing cost involved in case of packed phenol. It is requested that such information may kindly be taken into account while calculating non injurious price for packed phenol.

The statement of opposing interested parties that HOCL is the only producer is factually incorrect as it is a well known fact, known to opposing interested parties also that the HOCL is one of the three producers of Phenol in India.

The installed capacity of the petitioner is 40000 MT. At the time of making application for safeguard duty, the domestic industry has draw adjustment plan and accordingly necessary changes have been made. Accordingly, effective capacity of the domestic industry is 49000 MT.

Views expressed by M/s Schenectady Herdillia, Mumbai.

25. Our company has pioneered the manufacture of phenol in India by the synthetic route and have been manufacturing this product since 1968. Apart from this, for the last over a decade, we have been manufacturing derivatives of phenol as well. We have been exporting significant quantities of phenol derivatives for which we had imported phenol duty free. All our imports of phenol during the Investigation period were under DEEC Scheme/Advance License.

We have already the supported the application made by Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL) for levy of Anti Dumping duty on phenol imported from the subject countries.

The data provided by us is open for verification by the officers of your Honorable Directorate. The data provided by us for the investigation period clearly shows that we have suffered injury due to dumping.

Since major portion of phenol derivatives manufacture by us is exported, the captive consumption for our own phenol (for manufacture and sale of derivatives in domestic market) is a very small portion of our domestic production.

Our company has no objection for being included as a part of the domestic Industry. Likewise, our company has no objection to being excluded from the domestic industry for the purpose of said investigation.

We learn that M/s HOCL are praying for increase in Anti-Dumping Duty on phenol imported in packed condition. We support this prayer of HOCL.

M/s Merisol S.A South Africa

26. Use of data filed by Merisol at para43 page 37 of the Preliminary Findings, the Hon'ble Designated Authority has noted that the 'the authority has, therefore, taken the port data furnished by Kandla Customs for imports of subject goods from EU and all bulk imports from South Africa. It is submitted that Merisol is the only exporter of this product under consideration from South Africa. The data filed by Merisol is true and complete representing all drum and bulk imports from South Africa, thus, it is submitted that the exporters data be accepted as full and complete and all calculations be made on this basis.

The petitioners cite the example of Polyol as a basis for the co-existence of Anti dumping duty and safeguard duties. However, it is clear from the sequence of events that at the time of discontinuance of safeguard duties, no anti dumping duty had come into force.

At the outset, it must be stated that the Hon'ble Designated Authority has erred by relying only on the information provided by M/s. HOCL and has ignored the data of M/s. Schenectady Herdillia by ruling them out of being domestic industry. It may please be noted that M/s HOCL has historically been an inefficient enterprise and basing all the injury calculations on the HOCL data is causing extreme hardship to the consuming industry.

M/s Mitsui &Co, Singapore

27. In para 35 of the preliminary findings, the information related to cost of production, net sales realization and profit and loss has been indexed with reference to the year 1998-99. In this connection, we wish to submit that the figures of the period of investigation cannot be compared to 1998-99 as a proper analysis would require that the comparisons are made with the immediately preceding period unless reasons to the contrary are demonstrated.

M/s Atul Ltd, Mumbai

28. We wish to mention here that Atul Limited is a Rs.600 crore turnover company belonging to the Lalbhai group having diversified interests in various fields. Our Agrochemicals division manufacturers wide range of pesticides (herbicides and fungicides) and cater to domestic as well as export market. We are the major end user of phenol in pesticide industry

and would severely be affected due to proposed imposition of anti dumping duty on phenol imports.

Authorities have already accepted in para 8 of part D that HCL is another major producer in the country and supports the petition. We submit that here that in all fairness, the same yardstick should be applied for interpreting various provisions of the act and the Authorities should reconsider their exclusion from the investigation.

Imposition of Anti Dumping Duty does not serve public interest:

This would lead to heavy losses and in turn closure of the units.

Retrenchment of labour creating labour unrest/unemployment.

Reduction in export hence loss of valuable foreign exchange to the country.

M/s Foseco

29. We are one of the largest speciality chemical supplier to the Foundry and steel industries, mainly consisting of automotive, general engineering, railways, valves and associated small foundry ancillaries, who are catering to the auto manufacturers. As you are aware, due to continuous recession and the slack in the economy in the above mentioned foundries (viz. automotive, general engineering, railways, valves) our customers are unable to bear the increase in the input cost with the result we are forced to absorb the increased cost since we are unable to recover the same from the end users.

High prices of phenol has made the operational cost of the phenol user industry non-viable and same units are closing down.

It may be noted that the fluctuation in selling prices of phenol is result of supply and demand of phenol in market at a given time and not due to dumping. It can be seen that prices of phenol have since been increased by phenol manufacturers by Rs.4000 pmt and prices of acetone have also been increased by Rs.3500 PMT though there has been no increase in cost of raw materials.

M/s Kesar Petroproducts

30. We are manufacturers of Bisphenol-A (BPA) having rated capacity of 5000 TPA. Our requirement of phenol is 0.966 MT per MT of BPA. We also require Acetone (0.303 MT per MT BPA) which is a joint product of phenol. Thus, we are fully dependent on phenol manufacturers of our production programme and have been buying our requirements of phenol and acetone from HOC. We have developed strong business relationship

with HOC and have received highly satisfactory service from them in terms of deliveries, product information, terms of payment etc.

It is, however, experienced that price of phenol as well as acetone are very frequently revised upwards under a joint strategy followed by the two phenol manufacturers. For every increase of Rs.1000 in the price of phenol, the manufacturing cost of BPA goes up by Rs.1000 per MT. We are not able to pass on these increases in the cost of production to our customers since BPA is available in the international at a very competitive price and in order to retain our customers we have to absorb such increases which result in our operations becoming unprofitable.

M/s Ficom Organics

31. We were one of the largest manufacturers of Alkyl Phenols in India since 1983 to 1998 and were consuming large quantity of phenol from M/s. Hindustan Organics Chemicals Limited, (HOCL), Cochin. However, in the process of globalization, import duties have been reduced drastically from original level of 100% to 30% on Alkyl phenols thereby opening up the gates of cheaper imports of Alkyl phenols in to India from nearby countries. We could not compete them as we had no direct/indirect protection and also no control on phenol price as there were only two manufacturers of phenol.

We have not been able to operate the plant at full capacity as phenol supply from HOCL is erratic.

When Indian manufacturers are not able to meet domestic demand there is no alternative for the consumers of phenol but to import and if anti dumping duty is levied in such a situation, especially manufacturers like us who will be forced to once again shut their plant due to high cost of their finished goods.

International prices are currently ruling around US \$ 750/MT. At such a high price coupled with local customs duty, safeguard duty, special additional duty and storage cost we do not see any justification of still to levy anti dumping duty as this will seriously affect the consumers of phenol who will be forced to import due to non-availability from domestic manufacturers. In such a situation dumping of phenol in India is just not possible.

At this juncture, we would also request you to make anti dumping duty applicable on range of Alkyl Phenols being produced in India as we also need equal protection from other countries against cheaper imports.

Govt of Maharastra, Department of Energy

32. A number of representations have been received from manufacturers of downstream products based on phenol in Maharashtra to the effect that imposition of such duties will be extremely harmful to them and many of them may have to discontinue or drastically reduced their production since they are already selling their products below cost of production due to international competition.

It is requested that the matter may be viewed very carefully in the longer interest of phenol manufacturers as well as phenol users which is required in the interest of long term growth of phenol and phenol based industry.

M/s MPCL

33. It may be considered that like the petitioner, the phenol users are also domestic industry which requires market conditions in which it can survive. Thus, a view has to be taken on how to protect the interest of the domestic industry as a whole and not only the interest of the petitioners who have much more financial strength than the downstream small and medium sector users of the petitioners product.

M/s Pragati Chemicals

34. They have pointed out towards high profitability of Phenol plant and also the fact that HOC was an importer of phenol earlier. They have also pointed out the fact that like the petitioners, phenol users are also domestic industry, which requires market conditions in which it can survive.

Alta Laboratories

35. We are manufacturers of Bulk Drugs & Fine Chemicals mainly Salicylic Acid & its derivatives and phenol is our basic raw material. Prior to the year 1987 M/s. Herdillia Chemicals Ltd. was the sole manufacturer of phenol and we had to face all sorts of problems, which are inherent in a monopolistic supplier. With the advent of M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited, we were optimistic that the situation would improve, but it was only an illusion.

Like petitioner we are also a domestic industry and we require market conditions in which we can survive. Our main product Aspirin is subject to statutory price control under DPCO and Govt. expects us to sale this drug at reasonable price. Aspirin contributes more than 60% of our sales turnover. Thus, a view has to be taken on how to protect the interest of the domestic industry as a whole and not only the interest of the petitioners.

All India Association of Industries

36. We like to bring to your notice that one of our members has been seriously affected by way of heavy increase in input cost of phenol imported Europe, Singapore and South Africa.

The Speciality chemical is supplied mainly to the Foundry and Steel Industries, mainly consisting of automotive, general engineering, railways, valves and associated small industry ancillaries, who are catering to the auto manufacturers.

Hence, for survival of the foundry industry and foundry chemical suppliers, it is requested that the anti dumping duty should not be imposed and look forward to your valued response.

European Union

37. In addition, the European Commission would like to draw your attention to what seems to be an incoherent use of information. When determining whether exports from the EU were below the De Minimis threshold, the Designated Authority has used data as submitted by the petitioner allegedly due to the incompleteness of published data from the DGCI&S.

The assertion by the DA that 'the landed value of imports has been found to be significantly lower than the domestic industry's net sales realization should led to an even more demanding analysis of all factors causing injury, as determined under Article 3.4 of the WTO AD Agreement

Given the above, it is submitted that the current anti dumping investigation must be terminated.

Examination by the Authority regarding Current Price Increase, Current Supply constraints and Other Issues raised

1. It has been recognized by the Authority consistently that the imposition of anti dumping duty may have some impact on the prices of the product in the market. However, at the same time, the Authority has consistently held that the relative competitiveness of the users would not be affected with imposition of anti dumping duty. In the long run, Users would have assured supply of material at reasonable prices.
2. There have been arguments that the Indian Producers jointly resort to price increases. In case the Indian Producers increase the prices beyond a certain limits, there would be automatic check on the same by way of imports.

3. The fact that there is a single producer of subject goods in the country and does not, in any way, restrict the right of domestic producer to claim relief from the Authority against the dumped imports under anti-dumping rules. It has been accepted that anti-dumping duty is in the nature and form of providing a remedy against trade distorted practice of dumping. Further, anti-dumping duties do not propose to restrict or block imports from any sources and, therefore, the issue of domestic supply being short of the total consumption in the country, has no relevance. Also, since alternative sources of supply are available to the Indian users, the apprehensions of user industry, in this regard, are misplaced.
4. With regards the point raised by various interested parties about domestic industry being an inefficient supplier of the subject goods, the Authority holds that it has determined injury margin considering the optimum costs of the production.

C. Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Issues relating to the Dumping Margin

Views by M/s Mitsui & Co, Singapore and others.

38. It appears that the dumping margins worked out for various countries are not based on the actual cost data, but is based on constructed cost by the petitioner. There is a wide variation and the data requires proper scrutiny. We support the views expressed by the exporters M/s. Mitsui & Co. and Merisol as covered in the preliminary findings.

The Authority has worked out the dumping margin in case MPSTL at 28.75% of export price and for Mitsui & Co. at 28.5% of export price. In case of Merisol, South Africa the dumping margin is estimated at 42.24% for bulk sales and 36.48% for drum sales. It is however seen in case of European Union the dumping margin is taken as 97.72% based on the constructed cost of production as worked out by the petitioner. It is submitted that there cannot be such big difference in the dumping margin in Singapore, South Africa and European Union since the manufacturing process and cost of raw materials will not be so different as to justify such variation.

In response to the disclosure, M/s Kesar Petroproducts Ltd, submits that dumping margin appears to be very high and exporters of Phenol being major players in the world, domestic user would suffer serious injury if AD is levied based on such unrealistic dumping margin. On the issue of methodology of calculation of dumping margin, M/s Merisol, RSA, an

exporter has requested the Authority to reconsider the use of best information i.e 6(8) as the exporter had commercial constraints and challenges to part with the information requested. They have concluded that margin of dumping is inflated and erroneous, factors do not indicate injury, and causal link is not established and duty recommended is unjustifiably high. On the Issue of Dumping, M/s Mitsui & Co have highlighted the fact that issue of various appendices pertaining to the exporters questionnaire are not relevant to them as they are a trading company and hence their cost of production details are irrelevant.

Views of the Petitioner

39. Designated Authority sent initiation notification along with questionnaire proforma to the known exporters/producers in subject countries as also embassies of the subject countries in India. Only two companies from Singapore and South Africa and one trader from Singapore has responded to the Designated Authority. It is acknowledged in the preliminary findings that none of the exporters have furnished complete response in the form and manner prescribed and vital information was withheld by the exporters/ producers. Even after acknowledging that the exporter has not provided complete information, partial information has been accepted and dumping margin determined in the preliminary findings, resulting in lower dumping margin. It is worthy to note that the deficiencies in the response are in the nature of information consciously withheld by the exporters. Such being the case, acceptance of partial response is nothing but a bonus to the exporters for providing partial response.

40. The Designated Authority has determined separate dumping margin for

- a) Mitsui & Company,
- b) Mitsui Phenol Singapore

The response filed by Mitsui & Company states that the goods exported by the company were goods produced by Mitsui Phenol Singapore. This is in response to the question in the questionnaire with regard to identity of the producer. Followings are relevant in this regard: -

Since Mitsui & Company is not a producer of the subject goods, the company is not entitled for determination of dumping margin in isolation. At best, the company could seek fixation of anti dumping duty rate along with the concerned producer.

Since Mitsui & Company and Mitsui Phenol are affiliates, sales made by Mitsui & Company should be treated as sales made by Mitsui Phenol through its affiliates. Thus, Mitsui & Company is left with no sales which did not originate in Mitsui Phenol. Such being the case, Mitsui & Company could not have demanded a separate dumping margin.

The response filed by Mitsui Phenol is deficient to the extent that the company has not disclosed the fact that the exports to India were in fact carried out by Mitsui & Company. Thus, the same export transaction to India has been treated twice for determination of dumping margin - once as exports of Mitsui & Company and again as exports of Mitsui Phenol.

In response to the disclosure, the domestic industry on the issue of dumping from M/S Mitsui Phenol Singapore Ltd, maintains that the exporter has not furnished profit & loss statement of the company, which is very critical for determination of fair cost of production of the company (relevant for determination of whether the sales made in the domestic market of the exporting country were in ordinary course of trade. As regards Mitsui & Co, Designated Authority is fully justified in treating exporter as non-cooperative, as vital information has not been provided by the company though they maintain that There is no legal basis for the exporter to claim separate dumping margin in case the exporter is a trader. As regards M/s Merisol, since the exporter has not provided information desired by the Authority, it has been rightly held that the exporter has not cooperated in the investigations

Examination by the Authority

41. The Authority sent questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)©. The Authority received responses from the following exporters and exporters association.

Mitsui & Co Ltd. Singapore Branch.

Mitsui Phenol Singapore Ltd(MPSL), Singapore.

Merisol RSA (pty) Ltd, South Africa.

42. The Authority notes that M/s Mitsui & Company Ltd, Singapore Branch is a public company Incorporated and listed in Japan. They have exported to different importers in India during POI though they don't have any domestic sales. On the other hand M/s Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd, Singapore has exported to India during the POI through trading houses and they have made domestic sales also during this period.

Normal value and Export Price determination for Singapore:

43. Only M/s. Mitsui & Co Ltd, Singapore branch and M/s Mitsui Phenol Singapore Ltd, Singapore have responded from amongst the exporters of Singapore. M/s Mitsui Phenol Singapore Pte. Ltd. has given information relating to sales made in the home market and they have given an account of volumes sold along with invoice numbers and dates as per appendix I. They have added that they had sold phenol into India via Trading Houses and they have given customers names and addresses along with the details of shipment made. However they have not enclosed any profit and loss statement and balance sheets for the last three years in their submissions. The Authority also notes that the exporter has not submitted any information regarding financing and interests costs as required in the Appendix-8,9 and 10 in their submission as per their response to the questionnaire.

However the Authority notes that they have submitted the different transactions pertaining to domestic sales by giving invoice numbers, date volume sold and rate per unit in Appendix 1. The Exporter has also submitted information with regards to Appendix 3, which shows the export to India and domestic market sales. They have also submitted Appendix 4 and Appendix 5, which show sales price structure for exports to India and Sales price structure to Domestic sales. Further they have submitted the information under major heads excepting financial and interests costs as per Appendix 8 & 9 which gives the ex factory price for domestic sales and sales price for export to India. The Authority, for the purpose of preliminary determination, had accepted the data submitted by the exporter for normal value and export price determination by taking ex factory price for domestic sales as normal value on weighted average basis and ex factory price for sales to India as Export price also on weighted average basis subject to further verification and investigation. The Authority notes that they have not participated in the Public hearing conducted by the Authority and have not responded to the information sought during the preliminary findings and the subsequent letters written by the Authority to them to provide additional information as well. The Authority hereby declares the exporter as uncooperative and has constructed the normal value as per the facts available as per Rule 6(8) as the exporter has not submitted the relevant documents even after preliminary findings and subsequent letters written to them to provide the same. The Authority has therefore assessed the normal value for the exporter as per the best information available. The Authority has also accepted the data made available by the domestic industry with suitable normation and applicable

adjustments. The normal value for this exporter comes to US\$ **** per MT.

The Authority also notes that the firm has exported **** MT of subject goods to India at the rate of US\$ **** during the POI and ex factory price after making all adjustments come to US\$**** per MT. The Authority has allowed various adjustments as claimed by the exporter while arriving at the net export price at the ex. Factory level. These include discount @ US\$ ****per MT, Charges before FOB @ US\$****, after FOB adjustments @ US\$ **** towards overseas freight and @ US\$ **** towards overseas Insurance on per MT basis. The authority has determined normal value as US\$ **** per MT and Export price as US\$**** per MT. Accordingly the dumping Margin comes to US\$ **** per MT or 70.88 % of the export price.

M/s Mitsui & Co, Singapore

44. M/s. Mitsui & Co. Ltd. Singapore Branch has submitted similar arguments as made by M/s Mitsui Phenol Pte Ltd. Singapore. They have not submitted any information as per Appendix I of the questionnaire. However, as per Appendix III, they have confirmed that they do not any domestic market sales. They have given an account of exports made to India by giving customers names and addresses along with details of shipments made. They have given further information as regards sales price structure for exports to India and countries other than India. They have also calculated the price at the ex factory level for exports to India after making adjustments towards discounts/commissions and overseas freights. However they have not submitted any information towards appendix VII onwards. . However, the Authority had accepted the exporter's submissions for the limited purpose of preliminary findings subject to further verification and investigation. However, after the preliminary findings, the exporter was asked to submit the detailed information pertaining to the investigation along with the information listed in the preliminary findings but the exporter has submitted no relevant information till date. The firm has claimed that they made exports to third country and they had given an account of third country sales during POI. However, the Authority notes that the firm has not submitted any information listed in the letter written to them on 20th September 2002 with regards to the details of the raw material consumed and their expenses, complete details of the utilities, basis of determination of adjustments in the Appendix IV, V and VI, profit and loss accounts and balance sheet for the POI and three years prior to that etc. . As the required information has not been made available to the Authority, the Authority has been constrained to construct the

normal value as per the best information possible as per Rule 6(8). In this regards, the Authority has also accepted the data made available by the domestic Industry with applicable adjustments and suitable normation as has been done in the case with Mitsui Phenol Singapore Ltd. The Authority has therefore determined the normal value for Mitsui & Co. Ltd. as US \$ **** per MT. From the Exporters data, the Authority notes that the firm has exported **** MT of subject goods to India for a total value of US \$ **** during the period of investigation and their ex factory export price has been taken as US \$ **** pre MT after making adjustments towards discounts/commissions and overseas freight. The Authority has allowed discounts/ Commission @ of US\$ @ ****, overseas freight @ of US \$****, overseas insurance of US\$ **** as claimed by the exporter on per MT basis. The dumping margin for M/s. Mitsui & Co. comes to US\$ **** per MT or 60.56 % of export price

Other Exporters from Singapore

45. As regards determination of normal value for other non-cooperating exporters, the Authority has taken normal value as determined in the case of M/s Mitsui & Co. Singapore as mentioned in the preceding paragraph. As regards the export price the Authority has taken the lowest export price from Singapore to India during POI as the export price for non-cooperating exporters. The ex factory export price has been arrived after making adjustments towards commission, ocean freight and insurance. The authority has determined normal value as US\$ **** per MT and Export price as US\$**** per MT for non-cooperating exporters. The Dumping margin for Non-cooperating exporters comes to US\$. **** Per MT or 91.70% of the export price.

Normal Value and export price for Merisol RSA (pty), South Africa

46. M/s. Merisol RSA (pty), South Africa has responded to the questionnaire but has given incomplete information with regards to the different Annexure. As per the Appendix 1 they have submitted detailed information about the various sales in their domestic market by mentioning the invoice numbers, volume sold, sales value and rate per unit. They have also given invoice numbers of their domestic sales with quantity and rate per unit with respect to two principal grades, drum sales and bulk sales. In the Appendix 2 they have submitted an account of Phenol exports to India for the POI. They have backed this information by giving an account of sales to Indian customers by name giving a breakup of invoice values, ocean freight, insurance, commission, etc. In the Appendix 3 they have given an account of exports to India, sales to third countries and also sales in their domestic markets. They have

submitted Appendix 4 and 5 giving sales price structure for exports to India and sales price structure for their domestic sales. However they have not given sufficient information regarding their other product's quantity and value. However they have given an account of factory costs and profit of exports to India and for their domestic market with regards to their bulk and drum sales though they have not submitted required information about their financing and interests costs and they have not submitted net profit which they have added to their ex factory costs in the Appendix 8 and 9.

The Authority, after the public hearing, had asked the exporter to provide additional information especially relating to the costing and had also asked the exporter about their willingness to have the data submitted by them verified but the exporter has not replied to the Authority letter till date. The exporter was asked to furnish information relating to the basis of allocation of expenses to the product under consideration, basis of adjustments claimed in the various Appendices, copies of profit & loss and balance sheet for the POI and three years prior to that, net profit/loss before tax and unit selling price in the Appendix VIII and IX amongst others. As the exporter has not submitted the required data, the Authority has been constrained to determine the normal value as per the best information possible as per Rule 6(8). In this regards, the Authority has also accepted the data made available by the domestic industry with applicable adjustments and suitable normation. Normal Value for the bulk sales come to US\$ **** per MT and US\$ **** per MT from drum sales. As regards determination of export price, the Authority notes that the exporter has exported **** MT of subject goods to India for a value of US\$ **** at the rate of US\$ **** per MT for bulk sales and **** for US\$**** at the rate of US\$**** per MT for drum sales. The export price has been determined at the ex factory level after making adjustments towards inland freight @ US\$**** for bulk and US\$**** for drum sales on per MT basis. Packing @ US\$**** per MT in the case of drum phenol has been allowed by the Authority. Storage @ US\$****, handling, @ US\$ ****, others, @ US\$ ****, have been allowed for the bulk sales on per tonnage basis. As regards drum sales, commission has been allowed @ ****, inland freight @ US\$ ****, handling @ US\$ ****, others @ US\$ ****, overseas freight @ US\$ ****, overseas insurance @ US\$**** and shipping charges @ US\$ **** have been allowed on per tonnage basis. Thus after all adjustments, the export price has been worked out as US\$**** for bulk sales and US\$ **** for drum sales.

Dumping margin comes to US\$ **** per MT or 74.14% of the export price for bulk sales and US\$ **** per MT or 75.38 % of Export price for drum sales.

Normal Value and Export Price for other exporters from South Africa

47. As regards the export price, the Authority has taken the lowest export price from South Africa to India during POI as the export price for non-cooperating exporters both for bulk as well as drum sales. The authority has determined normal value as US\$**** per MT and US\$**** per MT for bulk sales and drum sales respectively as has been done in the case of M/s Merisol Pty Ltd and Export price as US\$ **** per MT and US\$**** per MT both for bulk sales and drum sales respectively for Non-cooperating exporters. Dumping margin comes to US\$ ***** per MT or 146.87% of Export price and US\$ **** per MT or 108.69% of export price for bulk and drum sales respectively.

Normal value and Export Price for European Union

48. The Authority notes that none of the exporters from EU has filed any response. As no information about domestic sales price structure of the subject goods, its cost of production in EU and other information as per the questionnaire has been furnished, the Authority has proceeded to rely upon the best available information for determination of normal value. The petitioners have claimed normal value in respect of EU on the basis of constructed cost of production. The Authority finds that none of the exporters have given any information to enable it to determine the normal value based on the domestic sales price. The Authority confirms, in the absence of any response from the exporters from subject countries in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject countries on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra.

Accordingly, the Authority has constructed the normal value on the basis of facts available with the applicable adjustments. The normal value so determined for EU is US \$**** per MT.

The Authority has taken into account transaction wise data from the information sent by Kandla Port Customs with regards to import from EU as this shows higher volumes. The Authority notes that the European Union has exported 11878MT for US\$5203737 at the rate of US\$ 438.09 per MT and after making adjustments for ocean freight, overseas insurance, commission, port expenses, inland freight, the export price comes to US\$ **** at the ex factory level. The Authority has made adjustments for US\$ **** as overseas freight, **** for marine insurance, ****% as commission, and US\$ **** each as port expenses and inland freight as per the best information available on per tonnage basis as per the information

made available by the petitioner. The Dumping margin comes to US\$ **** per MT or 77.87% of the export price.

Serial No	Country	Dumping Margin %
1.	European Union	77.88
2.	<u>Singapore</u> Mitsui & Co. Mitsui Phenol Singapore Ltd. Other Exporters	60.56 70.88 91.70
3	<u>South Africa</u> a. Merisol, RSA 1. Bulk sales 2. Drum sales b. Others 1. Bulk sales 2. Drum sales	74.14 75.38 146.47 108.69

D. Injury:

Issue regarding Injury Parameters and profitability and Causal Link:

Views of the M/s Merisol, South Africa, FMA, M/s Mitsui & Co, Mumbai, Pragati Chemicals Ltd. and others:

49. In para 33 of the preliminary findings, the Authority observed that the domestic industry has suffered injury on account of decline in production, capacity utilization and increase in inventory. The result is based on erroneous principles used for annualizing the period of investigation data. Comments have also been made that all the 15 injury parameters have not been examined by the Authority.

Various interested parties have commented upon the fact that HOCL made every high profit during the AM01. It is also said that manufacturers of Phenol are cash rich today as could be seen from their financial results of the last few years. They have also commented upon the fact that Authority has not examined upon the fact that there was a causal link between injury and failure of the domestic industry to export. It has also been pointed out that if the interest and depreciation of the Hydrogen peroxide plant is excluded then profit of the profit on phenol plant for AM 01 would have been 60.89 Cr.

In response to the disclosure, the EU has brought the attention of the Authority towards the fact that it is required by Article 7.4 of the WTO Anti Dumping agreements to apply the lesser duty rule and there is no indication in the disclosure that this has been done.

Views of the Domestic Industry:

50. The domestic industry has already provided detailed information to the Designated Authority as per parameters prescribed in application proforma. The same have been dealt by the Designated Authority in preliminary findings in so far considered relevant.

The specific parameters laid down under the Rules, such as imports from other countries, possible contraction in demand, export performance and technological factors have not caused injury to the domestic industry. Various parameters relating to the Injury include

Natural and potential decline in sales: -

a. Sales volumes of the domestic industry declined in the investigation period as compared to previous years. Sales of the domestic industry declined in spite of alleged excess demand in the country.

Profits:

b. The domestic industry was making profits till 2000-01 after imposition of safeguard duty. However, in 2nd quarter of investigation period triggered by the commencement of production in Singapore, the exporters from subject countries reduced their prices drastically. The domestic industry had no option but to reduce its prices even to a level of losses from a situation of profits. Analysis of

the quarterly performance shows that the profitability of the domestic industry kept declining within the investigation period.

Market share:

c. Share of subject countries in imports of Phenol in India was just 31.48% in 2000-01 and increased significantly to 79.43% in period of investigation. Share of the subject countries in demand of Phenol in India also increased significantly from about 5% in 2000-01 to above 40% in the investigation period. Further, the imports from subject countries increased significantly in relation to production of Phenol by the domestic industry.

Productivity:

d. The productivity of the domestic industry declined between 98-99 and investigation period even after reduction in number of employees. The productivity, which was 78.10 in 1998-99 declined to just 46.19 in the investigation period.

Return on investments

e. Return on investment for the domestic industry for the product under consideration was positive up to 2000-01. However, the same become negative in the investigation period.

Utilization of capacity

f. The capacity utilization of the domestic industry declined.

Factors affecting domestic prices.

Price undercutting

51. Landed value of imported material from subject countries was significantly below the selling price of the domestic industry causing severe price undercutting in the Indian market. Imports were undercutting prices to a level of more than 25%. Further, the significant price undercutting faced by the domestic industry was in spite of significant reduction in the prices by the domestic industry.

Price suppression/depression

52. The landed value of imports was not only below the selling price of the domestic industry but also below the cost of production and non injurious price for the domestic industry causing severe price suppression/depression in the Indian market.

The magnitude of the margin of dumping:

53. The dumping margin from the subject countries is not only more than de-minimus but also very significant. The impact of dumping on the domestic industry is significant.

Actual and potential negative effects on cash flow:

54. The cash flow which was negative in 1998-99 became positive thereafter till 2000-01. However, cash flow situation of the domestic industry deteriorated significantly in the investigation period after the imports from subject countries started in substantial volumes.

Inventories:

55. Stocks with the domestic industry increased to such an extent that the domestic industry had to take shutdown twice in the investigation period in order to reduce its inventory levels.

Employment:

56. The employment level with the domestic industry declined between 98-99 and investigation period even after increase in capacity.

Wages:

57. The domestic industry has no other option but to increase the wages for the employees due to the prevailing regulations in the country.

Growth:-

58. The domestic industry has enhanced capacity by de-bottlenecking in an effort to reduce the incidence of fixed costs. However, its impact has been nullified by the dumped imports. The domestic industry has not been able to grow in the investigation period with increasing demand in the market.

Ability to raise capital investments:

59. The domestic industry cannot think of raising fresh capital at this stage, given the poor performance of its product for some time.

Capacities with the exporters:

60. It is submitted that the exporters in the subject countries are holding significant surplus capacities. In fact, the new plant which has commenced commercial production in Singapore has exports as its primary thrust market. Vast Indian market is naturally quite lucrative to the exporters.

Significant increase in the rate of imports:

61. Imports from the subject countries have very increased very dramatically. These have shown very high growth rate in a very short period.
62. It may be seen from the above that Dumping from subject countries caused material injury to the domestic industry. The exports from the subject countries were causing threat of material injury.

Examination by the Authority

63. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti- Dumping Rules lay down that:

- a. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- b. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

The following parameters have been analyzed for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.

Sales Volume and Value

The Authority observes that there is a decline in the sales volume as well as the sales value in the POI as compared to the previous year. The unit price realization has also gone down by about 26% in the POI over the previous year.

Volume and Market Share of Dumped Imports

Country	European Union (Kandla)	Singapore (Exporters)	South Africa (Exporters)
---------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

	Port Customs)		information claimed confidential)		Information claimed Confidential)	
Year	Qty MT	% Share	Qty MT	% Share	Qty MT	% Share
2000-01	****	11.05	****	0.58	****	3.34
POI (9 Months)	****	29.13	****	32.30	****	14.80
POI Annualised	****	29.13	****	32.30	****	14.80

The Authority has examined the information regarding the volume of exports from the subject countries during the period of investigation and the preceding years. In percentage terms the imports from subject countries accounted for a market share of 64.3% in 1999-2000, 31.48% during 2000-01 and 76.23% during POI. When compared to the previous year 2000-01 the share in the market has shown a significant increase during the POI. The Authority notes that there has been a significant increase in the imports from the subject countries during the POI

Market Share of Imports from Subject countries			
Year	Imports From Subject Countries MT	Total Imports MT	% Share
1999-2000	18730	29128	64.3
2000-2001	4502	14298	31.48
POI Annualised	41441	54364	76.23

Market Share of Imports from Subject Countries (% of the Total Demand)

64. The Authority has calculated the total demand in the country by adding the total imports to the sales of the domestic industry as well as other producers of the product under consideration. The Authority notes that the imports from the subject countries could acquire a market share of 36 % of the total demand in a short span of 9 months.

Production & Issue of Capacity Utilization of the petitionerViews of M/s Merisol, South Africa, Foseco Ltd, Govt of Maharashtra, FMA, and others.

65. It is a matter of public domain information from the Balance Sheets of HOCL, that the installed capacity is much lower than the effective capacity, the effective capacity claimed by the Petitioners is 45000 to 49000 MTPA. However, the balance sheet and the information put out by the Government of India for the privatization of the Petitioner, clearly, states that the installed capacity is 40000 MTPA. In the light of the above, the Petitioners must be put to strict proof of their claim. It is submitted that the information of the Government of India and auditors be accepted and the injury parameters be reworked using these figures. Rated capacity of HOC's phenol plant is 40000 TPA as per its published Balance Sheet. HOC has been achieving very high capacity utilization based on its rated capacity.

Views of the Petitioner

66. Installed capacity of the domestic industry was 40000 MT. After restructuring plan undertaken by the company, the company has effectively increased its capacity to 49000 MT. Therefore, the effective capacity of the company now is 49000 MT. With regard to capacity mentioned in the Annual Reports and dis-investment proposal, please note that the capacity mentioned therein (40000 MT) is installed capacity, whereas the capacity relevant for the purpose of anti dumping investigations is effective capacity (which is 49000 MT). It is submitted that 'installed capacity' and 'effective capacity' need not be the same. Installed capacity refers more to what was the capacity installed by the company, whereas the effective capacity refers to what is the maximum possible production which the company can effectively achieve.

Examination by the Authority

67. The Authority has taken note of the various submissions made by the interested parties regarding the reworking of the capacity utilization on the basis of the installed capacity of the petitioner. The Authority has also taken note of the petitioner's plea that after de bottlenecking, their effective capacity has increased and they are in a position to produce more than the installed capacity. The Authority has now worked out the capacity utilization of the domestic industry based on their installed as well as the effective capacity and it concludes that the capacity utilization of the domestic industry has worsened in the POI.

68. Price Undercutting and Price Underselling

Price Undercutting during POI			
Country	Net selling Price petitioner	Landed Price from subject country	Price Undercutting
EU	****	****	****
MPSI, Singapore	****	****	****
Mitsui & Co, Singapore	****	****	****
Merisol, Bulk, S. A.	****	****	****
Merisol drum, S.A	****	****	(-) ****

Price Underselling during POI			
Country	Non Injurious Price of petitioner	Landed Price from Subject country	Price Underselling
EU	****	****	****
MPSI, Singapore	****	****	****
Mitsui & Co, Singapore	****	****	****
Merisol bulk, South Africa	****	****	****
Merisol drum sales, S.A	****	****	****

69. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject countries during the POI with the net sales realization and has found that there has been a significant price under-cutting by the dumped imports. The landed value of imports has been found to be significantly lower than the domestic industry's net sales realization.

The Authority has also examined the claim of the petitioner that the domestic industry is suffering on account of the losses. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the Non-injurious price for the product under consideration and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant incidence of price underselling causing injury to the domestic industry. The imports have had significant suppressing/depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price in view of the dumped imports.

Selling Price / Profitability

70. The authority notes that selling prices of the domestic industry is significantly below the price, which would have permitted the domestic industry, a fair recovery of its cost of production and earn a reasonable return. Thus, the dumped imports have prevented the domestic industry from effecting legitimate price increase to realise a reasonable price. The industry has suffered material injury on account of depressed selling prices resulting in non-recovery of cost of production and thereby suffered financial losses.

Other injury parameters evaluated by the authority are as follows:

71. The employment levels of domestic industry have not undergone any significant change during the period of investigation. There is a marked rise in the closing stocks during POI indicating that there is a significant change in the inventory position of the domestic industry during the period of investigation.

Some exporters/Users have opined that during the POI, HCL has made profits and HOCL has incurred loss. They wanted the Authority to examine this issue. They have also argued the fact that data pertaining to the M/s Herdillia Chemicals Ltd (HCL) should be examined and they should not be allowed to take the benefit of Anti Dumping Duty. Though the Authority has excluded the HCL as part of the domestic Industry as mentioned above, it has examined the records submitted by HCL and has come to a conclusion that there is no truth in the submission that HCL made profits during the POI. In fact they had made a loss of Rs **** during POI.

Month/Year	Cost of Production (HOCL) Rs/ MT	Net sales Realisation (HOCL)Rs/ MT	Profit/Loss (HOCL) Rs/. MT
98-99	100	100	100
99-00	103	94	48
2000-01	133	140	173
Apr.01- June-01	135	132	115
July 01-Sept 01	132	107	-13.5
Oct.01 – Dec 01	140	87	-170
PERIOD OF INVESTIGATION	135	108	-25

Indexed figures considering 1998-99 as 100.

The Authority also notes that the depreciation of the hydrogen peroxide plant has not been taken into account in working out the profitability of this plant.

Cumulative assessment of injury

72. As per annexure-II (iii), in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess

effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article --- and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%. The Authority has also found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article and has found that there is a cumulative effect of injury by imports of subject goods on the domestic industry.

E. CAUSAL LINK

73. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts: -

a. The Authority observes that there is a single market for the subject goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the domestic industry. Decline in demand is not a factor causing injury to the domestic injury. The imported subject article and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Thus, pricing becomes the most important factor determining purchase of the article from either imported sources or domestic sources.

b. The imports from Subject countries undercut and suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

c. The Authority has also examined that demand of the subject goods have increased during the POI and has not found any sign of contraction of demand, changes in the pattern of consumption, trade restrictive practice of and competition between the foreign and the domestic producers and development in technology. In view of the above, the Authority determines that the dumped imports, through the effect of dumping, have caused material injury to the domestic Industry.

d. The landed value has been determined for the subject goods after adding onto the weighted average c.i.f. export price, the applicable level of customs duties (except duties levied under Section 3, 3(A), 9, 9(A) and 1% towards landing charges.

e. While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual cost of production of the subject goods to determine optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of

investigation. For calculation of injury margin, it has compared the ex-factory non-injurious price determined for the period of investigations with the landed value of the imported goods.

74. Duty up to dumping margin:

The Authority recommends the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

F. CONCLUSIONS

75. The Authority has, after considering the foregoing, concludes that:

(i) Phenol or product under consideration has been exported to India from subject countries below its normal value;

(ii) The Indian industry has suffered material injury;

(iii) The injury has been caused by the dumped imports from subject countries;

(iv) The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty on all imports of Phenol from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority recommends the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports compared with the non-injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation.

(v) Accordingly, the Authority recommends that the definitive anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries. The anti-dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in col. 3 and the landed value of imports of Phenol falling under chapter 29 and 27 of Customs tariff, for all exporters/manufacturers from the countries mentioned in Col. 2 of the Table below:

Serial Number (1.)	Countries/exporters (2.)	Amount (US\$ Per MT) (3.)
1.	Singapore: a. Mitsui & Co. Ltd b. Mitsui Phenol Singapore Pte Ltd Other Exporters	710.84 710.84 710.84
2	South Africa a. Merisol RSA 1. Bulk Sales 2. Drum Sales c. Other exporters 1. Bulk Sales 2. Drum Sales	710.84 778.59 710.84 778.59
3.	European Union	710.84

vi). Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

76. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 24th June 2002.

77. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority